हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2022 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

04.03.2022/1100-05/SS-DC/1

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मन्त्री वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों/वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करता हूं।
2. मुझे वर्तमान सरकार का पांचवां बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता और हर्ष की अनुभूति हो रही है। गत चार वर्षों में हमारी सरकार ने अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद जन आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की अभूतपर्व गाथा लिखी है। आज हमारा प्रदेश विकास के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। गत चार वर्षों में हमारी सरकार ने विकास प्रक्रिया का लाभ प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाया है। हमारी सरकार ने 'उज्ज्वला', 'मुख्य मंत्री गृहिणी सुविधा योजना', 'प्रधान मन्त्री किसान सम्मान योजना', 'आयुष्मान भारत', 'हिमकेयर', 'सहारा', 'जनमंच' तथा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से चलाई जा रही अनेक योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा का प्रयास किया है।
3. हम माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सूत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य पूरे प्रदेश का एक समान विकास करना और हिमाचल वासियों को उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने का समुचित अवसर प्रदान करना है। हमारी सरकार के इन प्रयासों में केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग रहा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह के लिए दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

सेवा और सिद्धि के,
चार साल समृद्धि के।

4. हम जनता के सेवक हैं और जन सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे सभी संकल्प प्रदेश हित से प्रेरित है। हमारे इरादे बड़े हैं और हमारी सारी शक्ति इन पावन संकल्पों को सिद्ध करने में लगी है। हमें विश्वास है कि दिसम्बर, 2017 की तरह प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें फिर से मिलेगा और प्रदेश के विकास का क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा :-

मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूं,
मैं धरती का गीत सुनाने आया हूं।
चार दीये तेरी दहलीज़ पे हैं रौशन,
एक दीया मैं और जलाने आया हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमने चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और यह हमारा पांचवां बजट है तो इसका अभिप्राय इससे जुड़ करके है।

5. कोरोना की प्रथम लहर के समय प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव देखा गया परन्तु हमने तमाम कठिनाइयों और बाधाओं को पार करते हुए इस समस्या का सामना किया। यही कारण है कि कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के आने तक हमने स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया और हम इस महामारी से निपटने में सफल हो पाए। महामारी से पूर्व जहां प्रदेश में केवल 2 ऑक्सीज़न संयंत्र थे उनकी संख्या बढ़कर आज 48 हो गई है। इसी प्रकार आज प्रदेश में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक 5 हज़ार से अधिक Oxygen Concentrators उपलब्ध हैं। इस महामारी ने व्यक्तिगत स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सोच, समझ और कार्यशैली में दीर्घकालिक परिवर्तन किए हैं जो अभी भी जारी हैं। प्रदेश वासियों ने इस परीक्षा के समय धैर्य और साहस

का परिचय दिया है। इस महामारी में हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इस विकट काल में हमारी सरकार प्रदेश वासियों के साथ खड़ी है। हमने इस महामारी के समय जीवन को बचाने के प्रयास तो किये ही साथ ही आजीविका को भी बनाए रखा।

6. हमारी सरकार का जनता के प्रति समर्पण और घोषित लक्ष्यों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण में पहली और दूसरी डोज़ लगाने में देश में पहला राज्य बना। हमने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को भी उत्कृष्टता से प्रारम्भ किया है और वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज़ भी पूरी सफलता के साथ लगाई जा रही है। सितम्बर, 2021 में अपने वर्चुअल सम्बोधन में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा टीकाकरण अभियान में हिमाचल प्रदेश को 'चैम्पियन' राज्य की उपमा देना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। केन्द्र सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर उद्यमियों ने अतिरिक्त निवेश किया और आज हिमाचल प्रदेश में निर्मित मास्क, PPE किट और अन्य सामग्री दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि रूस में निर्मित 'स्पुतनिक' कोविड वैक्सीन का व्यावसायिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यह सफलता हमारी सरकार की निवेशक हितैषी तथा ease of doing business को बढ़ाने वाली नीतियों का परिणाम है। हमारा काम करने का तरीका यह है :-

मेहनत इतनी खामोशी से करो,
कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे।

04.03.2022/1110/केएस/एचके/1

7. कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार का हाथ पकड़ा एवं हमें भरपूर सहयोग दिया। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पूंजीगत निवेश के लिए दी। इस सहायता का उपयोग महत्वपूर्ण निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। चिन्हित कार्यों को अगले छः माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट में इस आबंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पूंजीगत कार्यों में अतिरिक्त निवेश के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति तो मिली ही है साथ ही रोज़गार के नए अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति इस सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

8. अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चतता के चलते आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान रहे हैं तथा मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी हुई है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ने "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना", "आत्मनिर्भर भारत", "मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना" के अंतर्गत तथा "Building and Construction Workers Welfare Board" के माध्यम से कमज़ोर वर्गों एवं व्यवसायियों के लिए खुले दिल से सहायता प्रदान की जिसके कारण महामारी के दुष्प्रभावों को बहुत हद तक कम किया जा सका।

9. भारत सरकार के प्रयत्नों के चलते वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान 7.3 प्रतिशत गिरावट (Negative Growth) दर्ज की गई थी। वर्ष 2021-22 में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 11.8 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

देश की अर्थव्यवस्था की यह त्वरित एवं प्रभावी "V Shape" रिकवरी का श्रेय हमारे उर्जावान प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी के अभिनव और साहसिक नेतृत्व को जाता है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था

10. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 के दौरान 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में पिछले वर्ष आई गिरावट के बावजूद इतनी वृद्धि हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 1 लाख 75 हजार 173 करोड़ रुपये रहेगा। अग्रिम अनुमानों के अनुसार ही वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 01 हजार 854 रुपये आंकी गई है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय से 51 हजार 528 रुपये अधिक है।

विकास बजट

11. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 से बजट के बदलते स्वरूप के निरंतरीकरण में भारत सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत एक Single Nodal Agency Account (SNA) खोलने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता राशि राज्य अंशदान सहित अब बहुत ही कम समय में कार्यकारी विभागों के बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में केन्द्र सरकार की समस्त 91 योजनाओं को इस व्यवस्था के अधीन लाया गया है। 30 राज्य एवं DBT योजनाओं को भी इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में लाया जाएगा।

12. वर्ष 2022-23 के लिए 12 हजार 921 करोड़ रुपये के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9 हजार 524 करोड़ रुपये के

04.03.2022/1110/केएस/एचके/3

प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2 हजार 400 करोड़ रुपये तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 856 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं।

13. वर्तमान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं की DPRs बनाने तथा उनको नाबार्ड के Rural Infrastructure Development Fund(RIDF) के अंतर्गत स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

04.03.2022/1115/केएस/एचके/1

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में 3 हजार 200 करोड़ रुपये की लागत से 779 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई थी जबकि हमारी वर्तमान सरकार द्वारा प्रथम चार वर्षों के कार्यकाल में ही 3 हजार 452 करोड़ रुपये की लागत की 826 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवा ली गई हैं।

14. हाल ही में माननीय विधायकों के साथ दो दिवसीय बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में माननीय विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूंः-

- नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं क्योंकि सभी माननीय विधायकों की ओर से इस बात के लिए बार-बार आग्रह आ रहा था कि हमारी लिमिट कुछ क्षेत्रों में एग्जॉस्ट हो गई है और ऐसे में इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए। हमने इसको बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये किया है। जो कि 2017-18 की सीमा से लगभग दोगुना है।

- नाबार्ड से पोषित किए जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं में वर्ष 2022-23 से माननीय विधायक "रोपवेज़ परियोजनाएं" सम्मिलित कर सकेंगे।
- "विधायक क्षेत्र विकास निधि" से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में "द्वार" इत्यादि बनाने की अनुशंसा कर सकेंगे।
- "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" के अंतर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इस वृद्धि के साथ ही वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस निधि में कुल 90 लाख रुपये प्रति विधान सभा चुनाव क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी जो कि लगभग दोगुनी है।

04.03.2022/1115/केएस/एचके/2

- "विधायक एच्छिक निधि" को 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण करवाना चाहूंगा कि जब मेरी सरकार आई थी तो यह राशि 5 लाख रुपये थी और हमने दोगुना से ज्यादा इसको बढ़ाया है। सभी माननीय विधायकों की जो अनुशंसा थी, जो मांग थी हमने उसको पूरा करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगाः-

लहरों की खामोशी को,
समन्दर की बेबसी न समझ।
जितनी गहराई अंदर है,
बाहर उतना तूफ़ान बाकी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

तीन निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उपभोक्ताओं को इनसे निम्न लाभ प्राप्त होंगे :-

- नये कनेक्शन पर एक वर्ष में 3 निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे।
- जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ एक सिलेंडर लिया हो उन्हें दो अतिरिक्त मिलेंगे।
- जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ दो सिलेंडर लिए हों उन्हें एक अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस संदर्भ में काफी जगह से जो आग्रह या सुझाव आए हैं। उसमें कुछ का कहना है कि हमें डी0बी0टी0 मिलना चाहिए और कुछ का कहना है कि सिलेंडर चाहिए। लेकिन हमने जो बजट में प्रावधान किया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने सिलेंडर का जिक्र किया है। अगर इसमें सुझाव की दृष्टि से इस तरह से बात बनेगी कि हमें डी0बी0टी0 करना चाहिए क्योंकि काफी लोग इस तरह से भी चाहते हैं; तो इस पर भी विचार करेंगे। मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि वर्ष 2022-23 में इसके लिए 70 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 50 करोड़ रुपये अधिक हैं।

माताओं, बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट,
'गृहिणी सुविधा योजना' खुशी लेकर आई है।
हिमाचल बना देश का पहला धुंआ मुक्त प्रदेश,
जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है।

16. प्रदेश में वर्तमान में अनाज़ की बिक्री के लिए कोई भी विशिष्ट मण्डी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में पैदा होने वाले अनाज़ को पड़ोसी राज्यों में बिक्री के लिए भेजने में मुश्किलें आईं। प्रदेश में आगामी रबी सीज़न में 11 स्थानों पर अनाज़ की खरीद शुरू कर दी जाएगी जिसमें खरीद संबंधी सभी सुविधाएं जैसे ग्रेडिंग व सफाई के लिए मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीनें, कवर्ड तथा खुला नीलामी मंच, क्रेट्स, टैंट, पार्किंग, किसानों को बैठने के लिए उचित स्थान आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। 15 करोड़ रुपये की लागत से 4 नई अनाज

मण्डियां रामपुर(ऊना), मज़ारी(बिलासपुर), रियाली एवं मिलवा(कांगड़ा) में स्थापित की जाएंगी।

कृषि

17. अध्यक्ष महोदय, कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बहुत सम्बल प्रदान किया है। वर्तमान वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान है जोकि बहुत उत्साहवर्धक है। पिछले बजट को प्रस्तुत करते समय मैंने कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों के लिए एक्सपर्ट ग्रुप के गठन की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार ने प्रो0 रमेश चन्द जोकि नीति आयोग के सदस्य हैं, की अध्यक्षता में इस एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। इसके अध्ययन के बाद संबंधित विभाग रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे।

18. वर्ष 2018-19 का बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय मैंने 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान (PK3Y)' योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इस योजना के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को गुजरात की प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक कृषि को अपनाने का आह्वान किया है। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश केमिकल मुक्त प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

- वर्ष 2022-23 के अंत तक कुल 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा।

- प्रदेश की सभी 3,615 ग्राम पंचायतों में प्राकृतिक कृषि का एक-एक मॉडल विकसित किया जाएगा, जिससे आस-पास के किसानों को प्रशिक्षित करने व प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।
- प्रदेश में कम-से-कम 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

टी सी द्वारा जारी

04.03.2022/1125/av/yk/1

मुख्य मंत्री जारी

- प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा तथा उनमें से श्रेष्ठ 50,000 किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि की पूर्ण सूचना एवं आंकड़ों के साथ एक Dynamic Online Web Portal विकसित किया जाएगा।
- प्रदेश की 10 मण्डियों में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा 2 स्थानों पर प्राकृतिक कृषि के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष मण्डी स्थापित की जाएगी।
- प्राकृतिक कृषि के उत्पादों की बिक्री के लिए देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश में चुने गए स्थानों पर बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसान भाइयों का आह्वान करते हुए यह कहना चाहूंगा कि :-

आओ मिलकर मुट्ठी बांधें,
धरती का श्रृंगार करें।
खेतों में हरियाली रोपें,
समृद्धि का संचार करें॥

19. गत वर्ष हमारी सरकार ने पहली बार कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों को एक निश्चित शोध ग्रांट देने की घोषणा की थी। माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाएगा तथा शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा।

20. पराला मण्डी को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है। फलों और सब्जियों के भण्डारण की सुविधाओं में और अधिक बेहतरी के लिए इस मण्डी में 60.93 करोड़ रुपये की लागत से 5,000 मीट्रिक टन की क्षमता का एक नया कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 1.5 हजार मीट्रिक टन की क्षमता का फ्रीज़िग चैंबर, 10

मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता की ग्रेडिंग पैंकिंग लाइन और एक मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता की Individually Quick Freezing (IQF) लाइन स्थापित की जाएगी।

21. किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलें इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में जायका चरण-2 परियोजना के तहत प्रदेश में 13 मार्किट यार्डों को और सुदृढ़ किया जाएगा जिस पर 31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

22. पिछले वर्ष बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए मैंने प्रदेश में एम फूल मण्डी की स्थापना करने की घोषणा की थी जिसे परवाणू में स्थापित किया गया है। मैं आगामी वित्तीय वर्ष में एक और फूल मण्डी स्थापित करने की घोषणा करता हूं जिस पर 3 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

23. हमारी सरकार ने हींग और केसर की खेती प्रायोगिक तौर पर शुरू की है जिसके प्रारंभिक परिणाम उत्साहवर्धक हैं। अब प्रदेश में दाल चीनी एवं मौंक फ्रूट की खेती को इंस्टिच्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर के सहयोग से पायलट

आधार पर आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा।

24. प्रदेश में मक्की और गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा प्रदेश की अपनी पहाड़ी किस्मों के संवर्धन के लिए मैं बीज उत्पादन के वर्तमान आबंटन को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्तम बीज उपलब्ध करवाने के लिए मैं 3 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान करने की भी घोषणा करता हूं।

25. मैं प्रदेश में पहाड़ी मक्की की किस्मों को उपभोक्ताओं तक वैल्यू एडिशन एवं उचित ब्रांडिंग करके पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की भी घोषणा करता हूं।

26. कृषि क्षेत्र में किसानों को बाजार से सीधा जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन किया जा रहा है। ये एफ0पी0ओज0 छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज बेहतर दाम पर बेचने के लिए एक सशक्त माध्यम हैं। अगले वर्ष 20 और एफ0पी0ओज0 गठित किए जाएंगे जिनमें से 10 एफ0पी0ओज0 केवल प्राकृतिक कृषि पर आधारित होंगे। इसके अतिरिक्त सहकारिता

टी सी द्वारा जारी

04/03/2022/1130/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

विभाग भी प्रत्येक विकास खण्ड में एक एफ0पी0ओ0 स्थापित करेगा। सहकारिता विभाग इन एफ0पी0ओज0 को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा।

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए 2022-23 में 583 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बागवानी

27. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देशभर में फ्रूटबाउल के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है। इस क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक बागवानी नीति तैयार की जाएगी एवं निम्न बिन्दुओं पर पहल की जाएगीः -

- फूलों की खेती का विस्तार करने के लिए आर्किड और सजावटी पौधों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और "पुष्प क्रांति" योजना के अंतर्गत 11 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।
- बी0 फ्लोरा के लिए विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और भारतीय मधु मक्खियों की किस्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए 4.50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- शीटाके और ढ़ींगरी आदि मशरुम की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए तथा मशरुम प्रोसैसिंग एण्ड कैनिंग के लिए 3 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- जामुन और मेवों की खेती के लिए क्लस्टर बनाएं जाएंगे।
- हाई डेंसिटी किस्मों का पौधारोण और इम्युनिटी बूस्टर वाली फसलों की शुरुआत की जाएगी।

28. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स की ऋणी है जिसके प्रयास एवं मार्गदर्शन से वर्ष 1916 में प्रदेश में सेब का उत्पादन आरम्भ हुआ तथा प्रदेश की बागवानी को एक नई दिशा एवं गति प्राप्त हुई। बागवानी क्षेत्र का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। श्री सत्यानंद का देहावसान हुए 75 वर्ष हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व एवं योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि उनकी कर्मभूमि शिमला जिला के कोटगढ़-थानाधार व आस-पास के क्षेत्र को 'सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल' बनाया जाएगा और इसका बहुआयामी स्वरूप बागवानी, पर्यटन व भाषा एवं संस्कृति विभागों के समन्वय से विकसित किया जाएगा।

29. अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्थानों पर प्रोसैसिंग एण्ड कैनिंग यूनिट्स के अतिरिक्त सी0ए0 स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं। 58 करोड़ रुपये की लागत से चच्योट, रिकांगपियो, ज्ञाबोंग और चम्बा में सी0एस0 स्टोर का निर्माण वर्ष 2022-23 में आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रोहडू, गुम्मा, जड़ोल, टिक्कर, टूटूपानी तथा भुंतर में बन रहे सी0ए0 स्टोर, ग्रेडिंग व पैकेजिंग हाउसिज का इसी वर्ष लोकार्पण कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 75 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा।

30. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के दौरान 91 करोड़ रुपये की लागत से पराला में बन रहे फ्रूट प्रोसैसिंग यूनिट में उत्पादन आरम्भ कर दिया जाएगा तथा परवाणू व जड़ोल में स्थित प्रोसैसिंग यूनिट का 17 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही पावंटा साहिब, कांगनी तथा शाट में बन रहे मार्केट यार्डस को सितम्बर, 2022 तक किसानों एवं बागवानों को समर्पित किया जाएगा। परवाणू में बन रहे मार्केट यार्ड को भी मार्च, 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इन पर 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

31. अध्यक्ष महोदय, बागवानी क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2022-23 में लगभग 9 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस पर 198 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

32. बागवानी परियोजना के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत शिलारू एवं पालमपुर में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए 18 करोड़ रुपये के प्रावधान को प्रस्तावित करता हूं।

04/03/2022/1135/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

पशु पालन/ गौ-संरक्षण

बागवानी क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 में 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मैं यहां कहना चाहूंगा कि

कौन कहता है कामयाबी किस्मत ही तय करती है।
इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है।

33. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिए गौवंश का संरक्षण आस्था का विषय है। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जिसमें हमने गौवंश सेवा का संकल्प लिया था। हमने न केवल विभागीय स्तर पर बड़ी cow Sanctuaries और गौशालाओं की स्थापना की है अपितु निजी भागीदारी से भी उत्कृष्ट गौ सदनों को प्रोत्साहन दिया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में बेसहारा गायें सड़कों पर दिखाई देती थीं। हमारे प्रयासों के चलते गौशालाओं और cow Sanctuaries में गौवंश की संख्या 6 हजार से बढ़कर 20 हजार हो गई है। हमें विश्वास है कि सरकार के प्रयासों तथा गैर-सरकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से हम पूरे प्रदेश में बेसहारा गौवंश की सेवा सुनिश्चित कर देंगे। मैं सभी समाज सेवियों का इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेशवासियों से भी आहवान् करता हूं कि वे गौवंश के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाएं। इस संदर्भ में यहां कहना चाहूंगा कि सरकार वर्तमान कानूनों में कड़े प्रावधान करेगी तथा यदि आवश्यकता हुई तो नया कानून भी बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब गौवंश दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं और यह अमानवीय कार्य है। इस वर्ष हमने सर्दी के मौसम में देखा कि बहुत-सारी गायें जो छोड़ दी गई थीं, वे पहाड़ों पर चली गईं और बर्फ गिरने के पश्चात उनकी बहुत बड़ी संख्या में दुःखद मृत्यु हुई है। इस दृष्टि से कानून को और संख्त करने की आवश्यकता है। मानवीय दृष्टिकोण इस संदर्भ में बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि कानून को और कड़ा करने की जरूरत पड़ेगी और ऐसे लोग जो अपना मकसद निकलने के बाद गाय को छोड़ देते हैं, जब वह दूध देना बंद कर देती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है।

34. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 में 5 बड़ी cow Sanctuaries एवं गौ सदन की स्थापना तथा हिमाचली पहाड़ी गाय के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट फार्म स्थापित करने की भी घोषणा करता हूं।

35. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए निजी गौ-सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 500 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 700 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस व्यवस्था को अब "गोपाल" के नाम से जाना जाएगा। सरकारी क्षेत्र के गौ-सदनों के अनुदान में आवश्यकतानुसार समुचित वृद्धि की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा कि :-

जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे,
इस दुनिया में हम सब खुशहाल कहां होंगे।

गाय के प्रति जो हमारा भाव है जिसको हम मां कहते हैं, वह आज की तारीख में कम हो रहा है। इस दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि हम गऊ की सेवा करें।

36. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए दत्तनगर तथा चक्कर (मण्डी) में प्रतिदिन लगभग 50 हजार लीटर क्षमता के दो मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट शुरू किए जाएंगे।

37. अध्यक्ष महोदय, विगत चार वर्षों में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवार के हितों की रक्षा के उद्देश्य से मैंने दूध खरीद मूल्य में 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। वर्ष 2022-23 के लिए भी मैं इसमें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं।

38. अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पहली बार 44 मोबाइल वेटरिनरी एम्बुलेंसिज चलाई जाएगी जिन पर 7 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। पशुपालकों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी।

पैरा 39 एन0एस0 द्वारा जारी ....

04-03-2022/1140/NS/AS/1

39. पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए 'रूरल बैकयार्ड शीप डवलपमैंट स्कीम' के अंतर्गत 2000 भेड़ ईकाइयां स्थापित की जाएंगी जिस पर 12 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

40. अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ की लागत से 'राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम' चरण-III के अंतर्गत 5 लाख गाय व भैसों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये की लागत से सैक्स सोर्टिड सीमन पर आधारित कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाएगी।

41. अध्यक्ष महोदय, 'मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना' के तहत कार्य कर रहे कई ग्राम पंचायत वेटरिनरी असिस्टैंट, वेटरिनरी फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति के पात्र हो गए हैं। पात्र पशुपालन सहायकों को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्कीम अथवा संबंधित नियमों में बदलाव किया जाएगा।

पशुपालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 में 469 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन

42. अध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता एवं संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2022-23 में 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में Biofloc मत्स्य पालन इकाई] ट्राउट हैचरी] मछली फीड मिल और बर्फ सयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में 20 हैक्टेयर में नए मत्स्य पालन तलाबों का निर्माण किया जाएगा।

43. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 के दौरान मछुआरों को आईस बॉक्स सहित 20 थ्री- व्हीलर और 80 मोटर साईकिल, 200 नावें और जाल अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। पुरूषों के लिए यह अनुदान राशि कुल लागत का 40 प्रतिशत तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 60 प्रतिशत होगी।

44. मत्स्य पालन क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्र के 500 युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

45. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के जीवनयापन को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसमें बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष कर दिया गया था। जिसका सीधा लाभ 3 लाख से

अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र व्यक्तियों को वर्तमान में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है।

46. उपरोक्त के अतिरिक्त गत 4 वर्षों के दौरान हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी करते हुए निम्नलिखित लाभ दिए हैंः-

- विधवाओं, एकल नारी तथा 70 वर्ष से नीचे वृद्ध जनों को मिलने वाली 700 रुपये प्रति माह की पेंशन को बढ़ा करके 1000 प्रति माह।
- 70 वर्ष से ऊपर वृद्ध जनों तथा 70 प्रतिशत अपंगता वाले दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन को 1100 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 1500 प्रति माह।
- 65 वर्ष से 69 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपये प्रति माह।
- कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजेंडर को मिलने वाली 700 रुपये प्रति माह पेंशन को बढ़ा करके 850 रुपये प्रति माह।

2017 तक प्रदेश में सवा चार लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही थी। हमने अपनी सरकार के चार साल के कार्यकाल के अंदर ही 2 लाख 20 हज़ार से अधिक नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की है।

47. हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 6 लाख 35 हजार लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40,000 अतिरिक्त आवेदनों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी ।

04-03-2022/1145/NS/AS/1

48. अभी हाल ही में प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता हेतु वार्षिक आय सीमा, जो वर्ष 2014 में 35,000 रुपये निर्धारित की थी, को बढ़ा करके 50,000 रुपये वार्षिक कर दिया है। इस निर्णय से 60,000 से अधिक अतिरिक्त लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा/एकल नारी और दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ मिलेगा।

49. मैं सहर्ष घोषणा करता हूं सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मैं, मेरी सरकार के दृष्टिपत्र में किए गए वायदों को पूरा करता हूं। सभी के लिए किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा घटा करके 60 वर्ष करने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि बुढ़ापा सबको आएगा और बुढ़ापा जब आता है तो साथ बहुत कम लोग होते हैं तो सरकार उनका साथी बन और सहयोगी बन करके उनका ख्याल रखने के लिए खड़ी हो, यह मुझे लगता है कि बहुत पुण्य का कार्य जिसको हमने अपने हाथों में लिया है। उस काम को पूरा करने के लिए एक बड़े संकल्प के रूप में आगे बढ़ते हुए 60 साल से ऊपर सभी को आय सीमा में छूट देते हुए पेंशन का प्रावधान करने की हम घोषणा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा कि

जहां सजदा हो बुजुर्गों का,

वहां की तहज़ीब अच्छी है।

जहां लांघे न कोई मर्यादा,

वो दहलीज़ अच्छी है।

50. अध्यक्ष महोदय, मैं 60 वर्ष से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों, कुष्ठ रोगियों एवं ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 1000 रुपये प्रति माह, विधवाओं,दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं एव एकल नारियों को दी जा रही पेंशन 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 1150 प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 1700 रुपये करने की भी घोषणा करता हूं।

इसके साथ 70 साल के ऊपर जो हमने पहली केबिनेट की बैठक में घोषणा की है जिनको अभी तक हम 1500 रुपये पेंशन देते थे उन सभी को अब 1700 रुपये पेंशन प्राप्त होगी।

51. अध्यक्ष महोदय, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की परिधि को संख्या एवं परिव्यय दोनों की ही दृष्टि से प्रभावी विस्तार किया है। परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 में 7 लाख 50 हजार से अधिक व्यक्ति इस योजना से लाभ उठा पाएंगे एवं वर्ष 2017-18 में इस पर होने वाला

450 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। लगभग तीन गुणा बढ़ोतरी इसमें हमारे कार्यकाल में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा योजना के परिव्यय में 3 गुणा वृद्धि की है।

4.03.2022/1150/RKS/DC-1

अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए इस बजट में घोषित लाभों का सार निम्न हैः-

<u>पेंशन में वृद्धि</u>

- ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 150 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलायें बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पात्र होंगी।
- 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुष बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के पात्र होंगे।

सबकी दुआओं को दिल में उतारना है,
हमको तो हर घर का चूल्हा संवारना है।

<u>महिला एवं बाल विकास एवं कमजोर वर्गों का कल्याण</u>

52. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश एवं राष्ट्र के निर्माण में माताओं और बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण एवम् Gender Equality के लिए तत्परता से

प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। नई पहल करते हुए वर्ष 2022-23 में एक अलग से Budget Statement सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस Statement में ऐसी सभी योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध हैं। इस statement के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा तथा उनमें महिलाओं से संवाद के पश्चात् आवश्यक परिवर्तन करने में सहायता मिलेगी।

53. मैंने पिछले बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय सदन को यह सूचित किया था कि हमारी सरकार बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कुपोषण एवं एनीमिया को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है तथा हम नीति आयोग के साथ मिलकर इस गम्भीर विषय पर एक स्टडी करवाएंगे जिसके आधार पर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा।

54. प्रदेश सरकार ने इस में सम्बन्ध डॉ० वी. के. पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, के साथ विस्तृत विचार-विमर्श प्लान बना लिया है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए एक नई "**मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना**" प्रारम्भ की जाएगी। यह योजना सात स्तम्भों पर स्थापित होगीः-

- बच्चों की शारीरिक वृद्धि में दो मूल बीमारियों डायरिया तथा निमोनिया का शीघ्र पता लगाना और उसका सही उपचार करना।
- कम वज़न वाले नवजात शिशु एवं कुपोषण से सम्भावित प्रभावित होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की गहन निगरानी व सतत् समीक्षा।
- पूरक पोषाहार के लिए उपयुक्त प्रोटीन युक्त आहार।
- बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं में एनीमिया के उपचार के लिए विशेष प्रयास।
- उच्च रक्तचाप और एनीमिया से पीड़ित गर्भवती व धात्री (दूध पिलाने वाली मातायें) की समय रहते पहचान और उपचार ।
- कुपोषित बच्चों का सही उपचार ।
- IEC और Monitoring पर विशेष बल।

55. यह योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के परस्पर समन्वय तथा प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के तालमेल से चलाई जाएगी। यह अति आवश्यक है कि सभी विभागों के मध्य सम्पूर्ण समन्वय स्थापित हो और इनके कर्मियों के मध्य नियमित संवाद हो जिसके आधार पर आवश्यक सूचकांकों का चयन हो। इसके लिए सुदृढ़ इंटर फेस पोर्टेबिलिटी (Interface Portability) और डाटा इंटर-ऑपरेबिलिटी (Data Inter-operability) सुनिश्चित की जाएगी तथा विस्तृत दिशा-निर्देशों सहित Monitoring Mechanism दो माह में जारी कर दिया जाएगा।

56. '**मुख्यमन्त्री बाल सुपोषण योजना**' के अंतर्गत मैं 65 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रख रहा हूं। भारत सरकार से इसमें अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होगा।

57. अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय बजट में महिलाओं और बच्चों को लाभ प्रदान करने के लिए सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण-2 योजना को नया रूप दिया गया है। मैं सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 18 हजार 925 आँगनवाड़ी केन्द्रों में से केवल 2 हजार 138 आँगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में चलाये जा रहे हैं। इस दिशा में पहल करते हुए में 1,000 नये आँगनवाड़ी भवनों के निर्माण की घोषणा करता हूं। भवन निर्माण भारत सरकार, राज्य सरकार और मनरेगा के परस्पर समन्वय से किया जाएगा व इस पर लगभग 70 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

4.03.2022/1155/RKS/DC-1

58. वर्तमान में प्रदेश में चल रहे आँगनवाड़ी केन्द्रों में से 6 हजार 718 आँगनवाड़ी केन्द्रों को मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इन मॉडल केन्द्रों में सलाइड, स्विंग, ब्लू मॉडल बेबी टेबल, कुर्सी इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मैं शेष बचे 12 हजार 207 आँगनवाड़ी केन्द्रों को भी चरणबद्ध तरीके से मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र बनाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 32 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, माता और बहनों के सम्मान में मैं इतना ही कहना चाहूँगाः-

नारी शक्ति है, सम्मान है,
नारी गौरव है, अभिमान है।
नारी ने ही यह रचा विधान है,
नारी को शत-शत प्रणाम है।

59. वर्तमान में '**विधवा पुनर्विवाह योजना**' के अन्तर्गत पुनर्विवाह को प्रेरित करने के लिए 50 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रति दम्पति देने का प्रावधान है। मैं इस अनुदान राशि को बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

60. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के लिए One Time Settlement योजना को उदार बनाया जाएगा एवं इसकी समय सीमा बढ़ाई जाएगी। अभी तक एक हजार से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। योजना की समय अवधि बढ़ने के फलस्वरूप 12 हजार से अधिक लोगों के लिए 12 करोड़ की ब्याज और जुर्माना राशि की settlement हो पाएगी। Himachal Backward Classes Financial Development Corporation के ऋणियों के लिए भी One Time Settlement Scheme बनाई जाएगी।

61. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभिन्न संस्थान जैसे बाल देखभाल संस्थान, जिला बाल संरक्षण इकाईयां, वृद्ध आश्रम आदि चला रहा है। इन सभी संस्थानों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से Top-up का प्रावधान किया जाएगा। यह Top-up तब तक मिलेगा जब तक कि भारत सरकार इन दरों में संशोधन नहीं करती।

62. '**मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना**' के अन्तर्गत प्रदेश के बाल-बालिका आश्रमों से निकले सभी ऐसे बच्चे जोकि आश्रम छोड़ने के बाद अपनी पढ़ाई जारी न रख पाए हों, को

स्वरोज़गार के लिए 20 हजार रुपये देने का प्रावधान है। मैं इस अनुदान राशि को बढ़ाकर 35 हज़ार रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

63. मैं वर्ष 2022-23 से राज्य के बेसहारा बच्चों पुनर्वास तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई "**मुख्यमन्त्री असहाय बाल पुनर्वास योजना**" आरम्भ करने की घोषणा करता हूं।

न जाने वो बच्चा किस खिलौने से खेलता है,
जो दिन भर बाजार में खिलौने बेचता है।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

04.03.2022/1200/बी.एस./एच0के0/-1

मुख्य मंत्री जारी...
मैं कहना चाहूंगाः-

न जाने वो बच्चा किस खिलौने से खेलता है,
जो दिन भर बाजार में खिलौने बेचता है॥

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

64. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" के अन्तर्गत लगभग 54 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 151 करोड़ रुपए की लागत से 26 विकास खंडों में 119 "जलागम विकास परियोजनाएं" स्वीकृत की गई हैं। इन्हें वर्ष 2022-23 में आरंभ कर दिया जाएगा।

65. '**मनरेगा**' में "**पंचवटी**" योजना के तहत 28 वाटिकाओं का निर्माण किया जा चुका है तथा अन्य पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2022-23 में दो सौ अतिरिक्त वाटिकाओं व पार्कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

66. 'मनरेगा' के तहत निजी व वन भूमि में वृक्षारोपण और बागवानी स्वीकार्य है। वर्ष 2022-23 के दौरान वन विभाग के सहयोग से मनरेगा के तहत वृक्षारोपण हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

67. अध्यक्ष महोदय, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गो पर निरंतर आवाजाही रहती है। इन सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालयों इत्यादि सहित 12 बहुउद्देश्यीय सुविधा केन्द्रों का convergence के माध्यम से प्रथम चरण में निर्माण किया जाएगा।

68. ग्रामीण क्षेत्रों में Solid and Liquid Waste Management हेतु प्लाज़मा तकनीक से चलने वाले प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण किया जाएगा। Plastic Solid Waste and Grey Liquid Waste Management के तहत आठ हजार गावों को लाया जाएगा। साथ ही सभी विकास खंडों को क्रियाशील प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 870 ग्राम पंचायतों के प्रधानों सहित 2,510 कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

69. छठे राज्य वित्तीय आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिबद्ध दायित्वों के भुगतान के लिए 352 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। जोकि वर्ष 2021-22 से 104 करोड़ रुपए अधिक है।

70. अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मैं सहर्ष निम्न घोषणा करता हूंः-

* अध्यक्ष, जिला परिषद को तीन हजार बढ़ोतरी के साथ 15 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कार्य काल में सात हजार

रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है।

- उपाध्यक्ष, जिला परषिद को दो हजार बढ़ोतरी के साथ 10 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार हजार रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है।
- सदस्य, जिला परिषद को एक हजार रुपए बढ़ोतरी के साथ छः हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कार्याकाल में 2,500/- रुपए की वृद्धि की गई है।
- अध्यक्ष, पंचायत समिति को दो हजार रुपए की बढ़ोतरी के साथ नौ हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्याकाल में चार हजार रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। यानी आज तक जितना मानदेय मिलता था, उसका 50 प्रतिशत इसे बढ़ाया गया है।
- उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 1500/- रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6,500/- रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्याकाल में तीन हजार रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। यह भी 50 प्रतिशत के करीब है।
- इसी प्रकार सदस्य, पंचायत समिति को एक हजार रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5,500/- रुपए प्रति माह मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्याकाल में 2,500/- रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है।
- प्रधान, ग्राम पंचायत को एक हजार रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5,500/-रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्याकाल में 2,500/- रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है।
- उप प्रधान, ग्राम पंचायत को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 3,500 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्याकाल में 1,300 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है।
- सदस्य, ग्राम पंचायत को 50 रुपए बढ़ोतरी के साथ तीन सौ रुपए प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्याकाल में 75 रुपए से प्रति बैठक की वृद्धि की गई है।

04.03.2022/1205/बी.एस./एच0के0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

71. अध्यक्ष महोदय, 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के अन्तर्गत कुल 32 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिसमें लगभग 2,50,000 महिलाएं जुड़ी हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि एक नई '**मुख्य मंत्री महिला सशक्तिकरण योजना**' के अन्तर्गत इन महिला सहायता समूहों को निम्न अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएंगीः-

* उन सभी स्वयं सहायता समूहों को, जोकि ग्राम संगठन से जुड़े हैं, को रिवॉल्विंग फंड के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 25 हजार रुपए की One Time अतिरिक्त राशि Top-up के रूप में दी जाएगी। इसमें इन समूहों को 25 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी।

*आगामी एक वर्ष के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तहत बने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना' व 'प्रधान मंत्री जीवन ज्याति बीमा योजना' के तहत शामिल किया जाएगा व इन बीमा योजनाओं के वार्षिक प्रीमियम क्रमशः 12 रुपए एवं 330 रुपए का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी।

*अध्यक्ष महोदय, Community Resource Person के काडर में कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को वर्तमान में अपने गृह खंड विकास क्षेत्र में कार्य करने पर प्रति दिन 350 रुपए मानदेय दिया जाता है। मैं इस मानदेय को 350 रुपए से बढ़ा कर 500/- रुपए प्रति दिन करने की सहर्ष घोषणा करता हूं।

* '**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**' के अन्तर्गत श्रेणी-। जिलों क्रमशः शिमला, मण्डी, कांगड़ा तथा ऊना में समय पर किस्त का भुगतान करने की व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा ब्याज उपदान देने के बाद इन समूहों को अधिकतम चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। शेष आठ श्रेणी-॥ जिलों में यह ब्याज दर सात प्रतिशत रहती है। मैं घोषणा करता हूं कि श्रेणी-॥ के आठ जिलों के स्वयं सहायता समूहो को भी श्रेणी-। के चार जिलों के समरूप चार प्रतिशत की दर से ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा

ब्याज उपदान देने के बाद जो भी अतिरिक्त ब्याज देय होगा उसे प्रदेश सरकार द्वारा Interest Subvention के रूप में वहन किया जाएगा।

72. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष प्रारंभ की गई **"स्वर्ण जयंती SHG सहयोग योजना"** एक नए प्रारूप में इस वर्ष भी जारी रहेगी। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

वर्ष 2022-23 में विभिन्न सहायता समूहों के लिए 65 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 1,662 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

शहरी विकास

73. अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शिमला में जनता की सुविधा के लिए वर्ष 2022-23 में 160 करोड़ रुपए की लागत से 59 परियोजनाएं तथा धर्मशाला में 166 करोड़ रुपए की लागत से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। शिमला में 104 करोड़ रुपए की लागत से तथा धर्मशाला में 65 करोड़ रुपए की लागत से नए कार्य आरंभ किए जाएंगे।

74. शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग के निर्माण के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि स्थानीय निकायों को शेष 50 प्रतिशत भाग वहन करना होता है। मैं सरकारी अंशदान को बढ़ा करके 75 प्रतिशत करने की भी सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा :-

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

04-03-2022/1210/वाई.के.-एन.जी. /1

मुख्य मंत्री..... जारी

पैरा संख्या 74 के पश्चात.....

सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना,

जो भी मन में हो वह सपना न तोड़ना,

कदम-कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको,

बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन न छोड़ना।

75. अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में '**मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजना**' आरम्भ की गई थी। इसकी लोकप्रियता के चलते मैं इस योजना को वर्ष 2022-23 में कुछ संशोधनों सहित जारी रखने की घोषणा करता हूँ जिस पर 5 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत शहरी बेरोज़गार युवाओं को रोजगार की गारंटी, पात्रता एवं अन्य शर्तों से सम्बन्धित विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।

76. अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अटल श्रेष्ठ शहर योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 3 नगर परिषदों और 3 नगर पंचायतों को '**अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार**' से सम्मानित किया जाता है। अब इस योजना का विस्तार नगर निगमों के लिए भी किया जाएगा।

77. Legacy Waste Sites को साफ करने के बाद इन स्थलों पर वृक्षारोपण एवं पौधारोपण करके इनका सौन्दर्यकरण करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसके अन्तर्गत इनको पार्क तथा पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

04-03-2022/1210/वाई.के.-एन.जी. /2

78. छठे राज्य वित्तायोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर मैं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिबद्ध दायित्वों के भुगतान के लिए 187 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं जोकि वर्ष 2021-22 से 24 करोड़ रुपये अधिक है।

79. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को भी निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँः

- महापौर, नगर निगम को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई है जोकि लगभग दोगुने के करीब है।
- उप-महापौर, नगर निगम को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई है।
- काउंसलर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई है।
- अध्यक्ष, नगर परिषद को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- पार्षद, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- प्रधान, नगर पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- उप-प्रधान, नगर पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- सदस्य, नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

शहरी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 713 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

04-03-2022/1215/वाई.के.-एन.जी. /1

मुख्य मंत्री..... जारी

गुणात्मक शिक्षा

80. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में हुए विस्तार के बारे में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सी पुस्तकों तथा रिपोर्टों में वर्णन मिलता है।

मेरे पिछले अभिभाषणों में घोषित शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं निम्न 6 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की घोषणा करता हूं जोकि इस प्रकार है

सूत्र-I : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन :-

- शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत चरणबद्ध ढंग से सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षायें आरम्भ की गई है। इनका और विस्तार किया जाएगा।

- सभी राजकीय माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में मिश्रित मोड के माध्यम से Real Time Online Teaching आरम्भ की जाएगी। इससे लगभग 6 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
- राज्य की सभी पाठशालाओं में एक नई "**श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना**" के अन्तर्गत प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी तथा राज्य के शीर्ष तीन स्कूलों को नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करता हूं। इसी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की तीन शीर्ष पाठशालाओं को भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

सूत्र-II : IT के माध्यम से गुणवत्ता सुधार :-

- विगत दो वर्षों में प्राथमिक से लेकर कॉलेज तक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मेरे द्वारा घोषित तीन योजनायें अपने उद्देश्य में सफल होती दिख रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रस्तावित है : (1) 'स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय जिसके अन्तर्गत 100 नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (2) 'स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय' जिसके अन्तर्गत 68 नये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा (3) 'स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट 'महाविद्यालय' जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय वर्ष 2022-23 में सम्मिलित किये जाएंगे। मैं 10 नये राजकीय वर्ष 2022-23 में इन तीनों योजनाओं को और अधिक बल देना चाहूँगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में IT की विशेष भूमिका होगी। इन तीनों योजनाओं पर 54 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

सूत्र-III : मेधा प्रोत्साहन :-

- वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जिनमें कई वर्षों से संशोधन नहीं हुआ है। इन सभी योजनाओं पर पुनर्विचार करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 'महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना', 'इन्दिरा गान्धी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना', 'कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना', 'डॉ0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना' तथा 'स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना' जिनमें 700 रुपये से लेकर 1,250 रुपये तक का प्रावधान है, को बढ़ाकर

1,500 रुपये प्रतिमाह अर्थात् 18,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। 'राष्ट्रीय मिलिटरी कॉलेज छात्रवृत्ति योजना' तथा 'सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना' में यह राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह अर्थात् 24,000 रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी।

- अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान Armed Forces में शहीद अथवा विकलांग हुए जवानों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। यह आश्चर्य का विषय है कि इस छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 1983 से कोई भी वृद्धि नहीं हुई है तथा अभी तक छात्रों के लिए मात्र 30 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह का ही प्रावधान है। मैं इस विसंगति को दूर करते हुए इस योजना में भी उपरोक्त वर्णित योजनाओं के समरूप वृद्धि करते हुए 1,500 रुपये प्रतिमाह अर्थात् 18,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा करता हूं।
- इसके अतिरिक्त मैं IRDP छात्रवृत्ति योजना, जिसमें वर्ष 1991 से कोई वृद्धि नहीं हुई है को पुनर्नामित करते हुए एक नई "**मुख्यमन्त्री विद्यार्थी कल्याण योजना**"

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

04.03.2022/1220/जेएस/एजी/1

करने की घोषणा करता हूं तथा इनमें वृद्धि भी प्रस्तावित करता हूं। मैं छात्रों के लिए इसे 300 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष करता हूं। महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए इसे 1 हजार 200 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रतिवर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2 हजार 400 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा।

- मैं कक्षा-3 के 50 मेधावी छात्रों के लिए एक नई "**बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना**" शुरू करने की भी घोषणा करता हूं। मैरिट के आधार पर चौथी और पांचवीं कक्षाओं तक 3 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- इन सभी योजनाओं में वृद्धि से 30 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन सभी योजनाओं पर 15 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे।

- राजकीय विश्वविद्यालयों में शोध छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें किसी भी स्त्रोत से कोई फैलोशिप प्राप्त नहीं होती। आर्थिक कारणों से ऐसे विद्यार्थियों को शोध कार्य करने में कोई बाधा न आए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं वर्ष 2022-23 से एक नई **"मुख्य मंत्री शोध प्रोत्साहन योजना"** के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की तिथि से शोध के प्रारम्भिक तीन वर्षों तक शोधार्थी को 3 हजार रुपये प्रति माह फैलोशिप देने की भी घोषणा करता हूं। यह योजना शोध के क्षेत्र में मेधावी विद्यार्थियों के लिए न केवल सहायक होगी बल्कि साथ ही उच्च स्तरीय शोध को भी बढ़ावा देगी।

सूत्र-IV : समाज एवं अभिभावकों की भागीदारी

- राज्य की शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु छात्रों के अभिभावकों तथा शिक्षकों के बीच एक वर्ष में कम से कम तीन दिन संवाद अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

04.03.2022/1220/जेएस/एजी/2

सूत्र-V : पर्यावरण एवं प्रकृति से परिचय

- सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में 50 राजकीय महाविद्यालय, 50 पाठशालाओं और 20 ITIs में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
- वन विभाग तथा आयुष विभाग के सहयोग से वर्ष 2022-23 में 200 राजकीय विद्यालयों तथा 50 राजकीय महाविद्यालयों में आयुष वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी जिनमें दुर्लभ औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों का रोपण किया जाएगा।

सूत्र-VI : रोज़गार परामर्श

- छात्रों के मार्गदर्शन तथा Career परामर्श की दृष्टि से सभी उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राजकीय महाविद्यालयों,

संस्कृत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में Career Guidance and Placement cell की स्थापना की जाएगी और जहां यह पहले से ही विद्यमान हैं, उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा :-

किताब और कलम हर बच्चे की तकदीर बदलेगी,

ज्ञान की ज्योति हिमाचल की तस्वीर बदलेगी।

81. अध्यक्ष महोदय, शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वर्ष 1970 में स्थापित हुआ था। विगत 52 वर्षों में प्रदेश के लिए यह एक मात्र राज्य विश्वविद्यालय था। मैं घोषणा करता हूं कि मण्डी में बन रहा 'सरदार पटेल विश्वविद्यालय' अप्रैल 2022 से कार्य करना आरम्भ कर देगा।

04.03.2022/1220/जेएस/एजी/3

82. अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिकारी शिक्षा विभाग में हैं और इनमें से कुछ संवर्गों के Service Matters लम्बे समय से लम्बित हैं। पिछले बजट में मैंने उन्हें सुलझाने की बात की थी। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि :-

- B.Ed तथा TET योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम TGT (संस्कृत) तथा TGT (हिन्दी) किया जाएगा।

04.03.2022/1225/जेएस/एजी/1

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत लम्बे समय से उस वर्ग की मांग थी। हमेशा इस बात को लेकर वे हमसे आग्रह करते थे और मैं समझता हूं कि इस निर्णय के साथ, इस घोषणा के साथ उनकी बहुत लम्बे समय से जो लम्बित मांग थी, वह पूरी हो रही है, उसका समाधान हो रहा है।

- प्रवक्ता (School Cadre) तथा प्रवक्ता (School New) श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता (School) स्कूल किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ था, मुझे लगता है कि इसके माध्यम से उनकी समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।
- इसके अतिरिक्त TGTs से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्याध्यापक बनने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र मे लिए वर्ष 2022-23 में 8हजार 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

83. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सुन्दरनगर स्थित जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आगामी सत्र से कम्प्यूटर साइंस में B.Tech तथा सिविल इंजीनियरिंग में M.Tech प्रोग्राम आरम्भ किए जाएंगे। कंडाघाट स्थित राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, तलवाड़ में फार्मेसी के डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किए जाएंगे।

84. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चार नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नामतः लाड़ाघाट, श्री नैना देवीजी, जिला बिलासपुर एवं कटौला, जिला मण्डी तथा धारटीधार और बेचड़-का-बाग, सिरमौर जिला में खोलने हेतु DPRs बनाई जाएंगी।

04.03.2022/1225/जेएस/एजी/2

85. अध्यक्ष महोदय, मैं प्लम्बिंग, वैल्डिंग, इलैक्ट्रिशियन तथा फ्रिज एवं AC मुरम्मत जैसी सेवाओं को प्रदेश की जनता को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक नई "**कौशल आपके द्वार**" योजना आरम्भ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये ट्रेड चल रहे हैं, उनके माध्यम से इन संस्थानों के

नज़दीक रह रहे उपभोक्ताओं को ये सेवाएं न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगाः-

जिसमें कौशल होगा, वही कुशल होगा
कौशल के दम पर ही, वह सफल होगा।

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं चिकित्सा शिक्षा

86. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उदार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त हुए 419 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2022-23 में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध 848 करोड़ रुपये को मिलाकर वर्ष 2022-23 के अंत तक भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 1 हजार 267 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध होगी। मैं प्रदेश की जनता की ओर से प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इस सहायता के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

87. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के पूरक के रूप में हमारी सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2019 से "मुख्यमंत्री हिमाचल हैल्थ केयर योजना-हिमकेयर" आरम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख 40 हजार लाभार्थियों को 218 करोड़ रुपये की लागत से निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं। मैं घोषणा करता हूं कि हिमकेयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें लोगों को कठिनाई आ रही थी कि हर साल रीन्यूअल करनी पड़ रही थी। उसके बाद कई बार इसको कुछ लोग नहीं कर पाते थे इसलिए तीन साल के लिए हमने इसके रीन्यूअल का पीरियड किया है।

04.03.2022/1225/जेएस/एजी/3

अध्यक्ष महादय, "हिमकेयर" में नए परिवारों का पंजीकरण जनवरी से मार्च माह में होता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि इस योजना में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरा वर्ष होता रहेगा। इसके अतिरिक्त हिमकेयर के अंतर्गत प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी

लाया जाएगा। जेल में जो हमारे सजायाफ्ता लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा।

88. प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर-द्वार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं एक नई "**मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक** (M3C)" योजना की घोषणा कर रहा हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

04.03.2022/1230-35/SS-AS/1

मुख्य मंत्री मोबाइल क्लिनिक, उसका शॉर्टकट में नाम (M3C) रखा है, योजना को शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक चलाया जाएगा। इसमें बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी उपकरण होंगे। इसमें एक डॉक्टर द्वारा अपनी टीम के साथ गांव में जाकर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसमें डॉक्टर एक पारिवारिक डॉक्टर की तरह कार्य करेगा। कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहने वाले लोगों के लिए यह योजना एक वरदान साबित होगी। इसको हमने अभी एक तरह से पायलट बेसिज पर 68 के 68 विधान सभा क्षेत्रों में शुरू करने का निर्णय लिया है। इसकी सफलता बेहतर होगी तो आने वाले समय में अगर इसमें और एक्सपेंशन करने की गंजाइश होगी तो उसको भी करेंगे।

89. हृदय रोगों से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत IGMC तथा RPMC Tanda में उपलब्ध कैथ लैब की सुविधा के अतिरिक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर तथा नाहन में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर कुल 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

90. कैंसर के मरीजों की सुविधा हेतु RPMC Tanda में पैट स्कैन एवं ब्रेकी थैरेपी (Brachytherapy) तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में पैट स्कैन एवं MRI की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। इस पर 61 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

91. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक में एक व्यापक स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र स्थपित किया जाएगा जहां दानकर्ताओं के दूध का संग्रहण करने एवं परीक्षण, संरक्षण तथा वितरण की व्यवस्था होगी जिससे उपचाराधीन नवजात शिशुओं को दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

04.03.2022/1230-35/SS-AS/2

92. 2022-23 में प्रत्येक स्वास्थ्य खण्ड में एक 'मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र' विकसित किया जाएगा जिसमें Indian Public Health Standards (IPHS) के मानकों वाली सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

93. इस समय प्रदेश में नेशनल एम्बुलेंस सेवाएं-108 के अंतर्गत 198 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। इनके Response time को कम करने के उद्देश्य से 50 नई एम्बुलेंसों का क्रय किया जाएगा जिस पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा :-

पूरा और निःशुल्क इलाज़ मिले सबको,
यह था हमारा सपना।
आयुष्मान भारत, हिमकेयर से,
बना स्वस्थ हिमाचल अपना।

94. स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के विशेषज्ञ कॉडर की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों क्रमशः नाहन, चम्बा, नेरचौक तथा हमीरपुर में फैकल्टी और अन्य श्रेणी के समुचित पद भरे जाएंगे।

95. कोविड के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा सराहनीय सेवाएं प्रदान की गईं। विगत वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों का व्यापक विस्तार हुआ है। उसको देखते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद हिमाचल प्रदेश में सृजित किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस बात को हम देख रहे थे कि जो हमारा डॉक्टर का काडर है वह लगभग 2400 के करीब है और वह पूरा-का-पूरा भरा हुआ है। हैल्थ सैक्टर में पिछले काफी अरसे से पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार में भी बहुत एक्सपेंशन हुई है। इसलिए यह बहुत आवश्यक था क्योंकि काडर को बढ़ाने की आवश्यकता थी तो 500 नए डॉक्टरों के पद सृजित किए जाएंगे ताकि दूर-दराज के इलाके में जहां

04.03.2022/1230-35/SS-AS/3

पर एक्सपेंशन की गई है, नए स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं, वहां पर डॉक्टर्ज उपलब्ध हो सकें। इस बात को सुनिश्चित करेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2022-23 में 2752 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

96. 2022-23 में हमारी सरकार 100 आयुष औषधालयों को Wellness Centres के रूप में स्तरोन्नत करेगी।

97. माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से 'योग' ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। हमारी सरकार योग के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमेशा ही प्रयासरत रही है। इसी श्रृंखला में आयुष विभाग द्वारा Aayush Wellness Centres में महिला एवं पुरुष योग प्रशिक्षकों के रूप में आरोग्य मित्र लगाए जाएंगे।

ऊर्जा/बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं

98. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर दिए जा रहे अनुदान को अग्रिम रूप से बिजली बोर्ड को अदा कर रही है जिस पर हमारी सरकार अगले वर्ष 500 करोड़ रुपये उपदान प्रदान करेगी। हमारी सरकार 1 अप्रैल, 2022 से 4.40 लाख ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं, जिनकी मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक है, उन्हें जीरो बिलिंग की जाएगी। 61-125 यूनिट तक खपत करने वाले 7 लाख उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा किसानों को राहत देने के लिए बिजली की दर 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट की जाएगी। इन रियायतों से बिजली उपभोक्ताओं को वार्षिक 100 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

99. हमारी सरकार प्रदेश में 24x7 विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार 12 अतिरिक्त HT योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक अतिरिक्त HT योजना को

2022-23 में शुरू किया जाएगा। बढ़ते लोड को देखते हुए मौजूदा प्रणाली में 393 MV क्षमता की वृद्धि की जाएगी जिससे वोल्टेज़ की समस्या कम होगी।

100. कम वोल्टेज की समस्या को समाप्त करने के लिए 33/11 KV HT केन्द्रों के निर्माण तथा मौजूदा 33/11 KV HT केन्द्रों की क्षमता के विस्तार हेतु 2022-23 में 23 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी जिससे संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।

101. 'मुख्य मंत्री रोशनी योजना' के अंतर्गत पात्र 12765 निर्धन परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इस योजना के तहत 2022-23 में 5 हजार परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे।

102. हमारी सरकार विद्युत वितरण नेटवर्क में मौजूद लकड़ी के खम्बों को सौ प्रतिशत बदलने हेतु प्रतिबद्ध है। 2022-23 में लगभग 20 हजार लकड़ी के खम्बों को लोहे के खम्बों से बदलकर इस कार्य को सम्पूर्ण कर लिया जाएग।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा :-

कुछ नहीं होगा अन्धेरों को बुरा कहने से,
अपने हिस्से का दीया खुद ही जलाना होगा।

103. हाल ही में घोषित ऊर्जा नीति में राज्य को 2030 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर बल दिया गया है। मेरी सरकार ने बड़े पैमाने पर पम्प भण्डारण परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है।

104. 2022-23 में 1000 मैगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं जनता की सेवा में समर्पित कर दी जाएंगी। साथ-ही-साथ 4 नई विद्युत परियोजनाओं साई कोठी-1 (15 मैगावाट), देवी कोठी (16 मैगावाट), साई कोठी-II (16.5 मैगावाट) तथा हेल (18 मैगावाट) का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा। इन परियोजनाओं का निर्माण जर्मनी के Development Bank KFW की सहायता से होगा।

04.03.2022/1230-35/SS-AS/5

105. 2021-22 में HPPTCL ने लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से अनेक ट्रांसमिशन लाइनें विकसित की हैं। 2022-23 में HPPTCL ने 7 Extra High Voltage (EHV) सब-स्टेशनों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 231 सर्किट किलोमीटर की कुल लम्बाई वाली 5 ट्रांसमिशन लाइनों तथा कुनिहार में संयुक्त नियंत्रण केन्द्र के निर्माण को पूरा किया जाएगा। इन 13 परियोजनाओं पर 645 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

04.03.2022/1240/केएस/डीसी/1

106. फ्रैंच विकास एजेंसी (AFD) से चांजू-III जल विद्युत परियोजना और दियोथल चांजू जल विद्युत परियोजना के वित्त पोषण के लिए सहमति दी है। AFD और भारत सरकार के बीच 800 करोड़ रुपये की राशि के क्रेडिट सुविधा समझौते (CFA) पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों परियोजनाओं की टैंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2022-23 में शुरू कर दिया जाएगा।

107. अध्यक्ष महोदय, स्पिति में बिजली की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली बोर्ड तथा Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) के संयुक्त उद्यम द्वारा काजा में 1 MWh बैटरी भंडारण प्रणाली सहित 2 MW क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना की जा रही है जो वर्ष 2022-23 में चालू कर दिया जाएगा।

108. अध्यक्ष महोदय, Grid Connected Roof Top सौर ऊर्जा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए तथा हरित ऊर्जा संकल्प हासिल करने हेतु मैं इन संयंत्रों पर वर्तमान उपदान राशि को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति KW करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। यह उपदान राशि घरेलू उपभोक्ताओं को भी देय होगी।

109. अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा की भी प्रदेश में बहुत सम्भावनाएं हैं, जिनका अभी समुचित दोहन नहीं हुआ है। SJVNL द्वारा वर्ष 2022-23 में 600 करोड़ रुपये के निवेश से 150 MW क्षमता की सोलर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में इससे युवाओं को रोज़गार के नए अवसर प्राप्त होंगे व सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी यह एक अच्छी पहल होगी।

जल शक्ति

110. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत अब तक 8 लाख 35 हजार नल कनैक्शन दिए गए हैं। इसकी तुलना में पिछले 72 वर्षों में 7लाख 63 हजार नल कनैक्शन दिए गए। हमारी

सरकार की यह अभूतपूर्व उपलब्धि जनवरी, 2022 तक 17 लाख 28 हजार ग्रामीण परिवारों में से 15 लाख 79 हजार परिवारों को पेयजल कनैक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। वर्ष 2022 के अंत तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनैक्शन दे दिए जाएंगे। वर्ष 2021-22 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1 हजार 500 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्र का पहला राज्य है जिसे वर्ष 2021-22 में इस योजना की चौथी किश्त प्राप्त हुई है। यानि पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन काम जल जीवन मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ने किया है।

111. "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनैक्शन प्रदान करने के बाद हमारी सरकार का लक्ष्य इन घरों को सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करने का है। इसके लिए Sensor आधारित तकनीक की सहायता से Real Time Basis पर पेयजल उपलब्धता तथा आपूर्ति की सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। यहां मैं यह कहना चाहूंगाः-

सोचने से कहां मिलते हैं,
तमन्नाओं के शहर,
चलना भी ज़रूरी है,
मंजिल पाने के लिए।

112. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत करते समय निर्मित Culterable Command Area (CCA) का केवल 45 प्रतिशत ही उपयोग हो पाता था। हमारी सरकार के सफल प्रयासों के चलते दिसम्बर, 2021 के अंत तक लगभग 51 प्रतिशत CCA का उपयोग किया जाने लगा है। प्रदेश में विद्यमान सिंचाई योग्य 3.35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से अब तक 1.87 लाख हैक्टेयर CCA का निर्माण किया जा चुका है। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार के उद्देश्य से वर्ष 2022-23 में 9 हजार हैक्टेयर CCA की

अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी तथा 6 हजार 500 हैक्टेयर CCA के लिए Command Area Deveiopment (CAD) किया जाएगा।

113. वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र की कार्य योजनाएं 80 के दशक में बनाए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कार्यान्वित की जा रही हैं। GIS के माध्यम से पूरे प्रदेश के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जिससे किसान बंधुओं को कम से कम समय में प्रभावी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सके।

114. वर्ष 2022-23 के दौरान निम्न 5 बड़ी पेयजल योजनाओं को जनता को समर्पित करने की घोषणा करता हूंः-

- 65 करोड़ रुपये की लागत से AIIMS, बिलासपुर और हाईड्रो इंजीनियर कॉलेज के लिए कोल डैम उठाऊ पेयजल योजना
- 110 करोड़ रुपये की लागत से टॉरखोला और अन्य गांवों के लिए पेयजल योजना
- 121 करोड़ रुपये की लागत से सिराज और बाली चौकी क्षेत्र की 19 पंचायतों के लिए पेयजल संवर्द्धन योजना
- 147 करोड़ रुपये की लागत से कमलाह व मण्डप क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लिए पेयजल योजना
- 56 करोड़ की लागत से डलहौजी के अन्तर्गत सलूणी, मंजीर, सुनदाई इत्यादि क्षेत्रों में संवर्द्धन पेयजल योजनाएं।

इन पांच योजनाओं में लगभग 1 लाख 25 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

115. वर्ष 2022-23 में ही निम्नलिखित 4 उठाऊ सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगाः-

- 6 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से भुंतर में जरीब्राधा योजना जिससे 256 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।
- 9 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से कुल्लू की ग्राम पंचायत बंदरोल के गिन्डौर, बनोगी, बबेली और सारी ग्राम समूहों हेतु योजना जिससे 417 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।
- जिला कुल्लू में ही 2 करोड़ 31 लाख रुपये की लागत से रेरी- मशगन योजना जिससे 93 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।
- ग्राम पंचायत, सिकवारी के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत की योजना जिससे 120 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी।

116. वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगाः-

- 20 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से काला अम्ब के लिए मल निकासी योजना।
- 14 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से त्रिलोकपुर-खैरी के लिए मल निकासी योजना।
- 13 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से परवाणु जोन-1 के लिए मन निकासी योजना।
- 4 करोड़ 23 लाख की लागत से ठियोग क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना।
- 2 करोड़ 81 लाख की लागत से कोटखाई क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना।
- 2 करोड़ 45 लाख की लागत से मैहतपुर के लिए मल निकासी योजना।
- 2 करोड़ 11 लाख की लागत से सुन्नी के लिए मल निकासी योजना।

117. वर्ष 2022-23 के दौरान एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी जिसमें भारत सरकार के Uniform Drinking Water Quality Monitoring Protocol के अनुसार लगभग 70 प्रकार के परीक्षण करने की सुविधा होगी।

अध्यक्ष महोदय, पानी का कुशल प्रबन्ध ही लम्बे समय तक इसकी उपलब्धता को बनाए रख सकता है। मैं यहां यह कहना चाहूंगाः-

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.03.2022/1250/av/hk/1

पानी हूं, जल हूं, नीर हूं मैं,
मुझे यूं न व्यर्थ बहाया करो।
बन पड़े जितना भी तुमसे,
मुझे उतना ही तुम बचाया करो।।

जल शक्ति विभाग के लिए वर्ष 2022-23 में 2,772 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़कें एवं पुल

118. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में लगभग 39,000 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कें हैं जिसमें से लगभग 32,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। गत वर्ष पंचायतों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कुल पंचायतों की संख्या बढ़ करके 3,615 हो गई हैं। इनमें से 3,556 पंचायतें सड़क के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। शेष बची हुई 59 पंचायतों में से 20 पंचायतों को वर्ष 2022-23 में सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।

119. वर्ष 2022-23 में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी जिनमें से 300 किलोमीटर की लंबी सड़कें तथा 1200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 23 पुलों का निर्माण किया जाएगा, 315 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज की जाएगी तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़

दिया जाएगा। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज़-iii के अंतर्गत 440 किलोमीटर लंबी 45 सड़कों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। इन 45 सड़कों की कुल लागत 552 करोड़ रुपये है। जून, 2023 तक शेष बची डी0पी0आर्ज0 भी भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जाएगी।

120. वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,592 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं। इनमें से 1,238 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च मार्ग लोक निर्माण विभाग के पास हैं। वर्ष 2022-23 में पीरियोडिकल रख-रखाव कार्यक्रम के अंतर्गत 110 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर काम किया जाएगा जिसकी लागत लगभग 700 करोड़ रुपये होगी।

04.03.2022/1250/av/hk/2

121. वर्ष 2022-23 में नाबार्ड के आर0आई0डी0एफ0 के अंतर्गत पोषित 180 किलोमीटर लंबी सड़कें, 235 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 395 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने तथा 25 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

122. वर्ष 2022-23 में लगभग 60 किलोमीटर लंबी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को सुरक्षित किए जाने का लक्ष्य है ताकि इन चिन्हित स्थानों पर दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।

123. अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली में बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव का समय आ गया है। वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित हैं :-

- मैं महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के पीरियोडिकल रख-रखाव की सीमा को 5 एवं 6 वर्षों से कम करके 3 वर्ष करने की घोषणा करता हूं ताकि अधिक-से-अधिक पर्यटक इन स्थलों पर भ्रमण का आन्नद ले सकें। इस पर 350 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़कों का 5 साल का जो मेंटेनेंस का विषय आता है उसमें यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और जो

क्लाइमेट चेंजिज हैं; जैसे सर्दियों में बर्फ पड़ती है और बरसात में भारी बारिश के कारण सड़कें जल्दी खराब होती हैं। इसलिए इस पीरियड को घटाकर 3 वर्ष करने से मैं समझता हूं कि पर्यटकों को अच्छी सड़कों की सुविधा प्राप्त होगी।

- डिफैक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद रख-रखाव के बजट का कम-से-कम 20 प्रतिशत भाग सड़कों के गड्ढों को भरने के उपयोग में लाया जाएगा।
- मैं घोषणा करता हूं कि सड़कों की मुरम्मत अथवा उन्नयन के समय, जहां पर भी सड़कों को उखाड़ कर दोबारा से बिछाने की आवश्यकता हो, को आधुनिकतम तकनीक से उखाड़ा जाएगा। उखाड़ी गई सामग्री को रीसाईकल करके उसे उपयोग में लाया जाएगा ताकि कम समय तथा कम लागत में यह कार्य किया जा सके।
- सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु जियो-सिंथैटिक मैटीरियल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- बर्फबारी के दौरान वाहनों को फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के लिए एक नए अधिक प्रभावी पदार्थ

टी सी द्वारा जारी

04.03.2022/1255/av/yk/1

Calcium Chloride Brine का इस्तेमाल किया जाएगा।

- 'हिमाचल प्रदेश सड़क उन्नयन कार्यक्रम' के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज और कल्वट्र्स का प्रावधान किया जाएगा।

124. अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों के आधार पर पिछली सरकार और हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में निर्मित सड़कों की तुलना करना चाहता हूं। हमारी सरकार के प्रथम चार वर्षों में ही पिछली सरकार के 5 वर्षों में निर्मित जीप योग्य सड़कें 33 किलोमीटर अधिक हैं, मोटर योग्य सड़कें 660 किलोमीटर अधिक हैं, पक्की सड़कें 1008 किलोमीटर अधिक हैं तथा 13 पुल अधिक हैं। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त क्रम को

जारी रखते हुए वर्ष 2022-23 में सड़कों एवं उनसे संबंधित सभी गतिविधियों के माध्यम से संक्षेप निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :-

- 1060 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण।
- 2065 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को पक्का करना।
- 990 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज।
- 75 पुलों का निर्माण।
- 20 पंचायतों, 80 गांवों तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य।
- 2200 किलोमीटर लंबी सड़कों की पीरियोडिकल मेंटेनेंस।

125. इन लक्ष्यों की पूर्ति से प्रदेश में वाहन योग्य सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक तथा पक्की सड़कों की लंबाई बढ़कर 34,000 किलोमीटर हो जाएगी।

इस नदी की धार से ठण्डी हवा आती तो है,
इस अंधेरे से इक सड़क उस भोर तक जाती तो है।

लोक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2022-23 में 4,373 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

04.03.2022/1255/av/yk/2

उद्योग/निजी निवेश

126. अध्यक्ष महोदय, 'मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना' रोजगार सृजन की अब तक सर्वाधिक लोकप्रिय योजना बन करके उभरी है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 457 करोड़ रुपये के निवेश से 2,800 उद्यमों में लगभग 8,000 युवाओं को रोजगर के अवसर मिले हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत यानी सभी केटेगरी की महिलाओं को पहले इसमें 30 प्रतिशत की व्यवस्था थी और

विधवाओं के लिए 35 प्रतिशत था। अभी मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगों को मिलने वाले अनुदान को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को तुरंत भूमि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पायलट आधार पर जिला कांगड़ा में 'मुख्य मंत्री स्वावलम्बन पार्क' स्थापित किया जाएगा। जिसमें 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट व शैड विकसित किए जाएंगे।

127. अध्यक्ष महोदय, 'औद्योगिक निवेश नीति-2019' औद्योगिक विकास के लिए, विशेषकर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों के लिए अनुकूल साबित हो रही है। मैं सहर्ष घोषणा करता हूं कि यह नीति दिसम्बर, 2022 के स्थान पर दिसम्बर, 2025 तक जारी रहेगी।

128. 'मैडिकल डिवाइस पार्क' की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के पक्ष में की जा चुकी है। नालागढ़ स्थित इस पार्क को विकसित करने के लिए वर्ष 2022-23 में कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस पार्क के विकसित हो जाने से विदेशों पर निर्भरता कम होगी, प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पार्क के विकास पर सरकार द्वारा 332 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

टी सी द्वारा जारी

04/03/2022/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

मुख्य मंत्री ... जारी

129. प्रदेश में रेशम उत्पादन की गतिविधियों से जुड़े लगभग 12 हजार किसान परिवारों की आय में वृद्धि के लिए Central Silk Board के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन कंवर्जेंस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

130. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा परिवहन के क्षेत्र की सभी कर व्यवस्थाओं के सफल सरलीकरण के पश्चात् वर्ष 2022-23 में इन करों का पड़ोसी राज्य के अनुरूप

सरलीकरण किया जाएगा। सड़कों पर वाहन एवं यात्री सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से प्रत्येक आर0टी0ओ0 को एल्कोहन सेंसर स्पीड राइडर क्रैश इंवेस्टिगेशन लैब तथा ई-चालान व्वयस्था से सुसज्जित Interceptor Electric वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन वाहनों में उपस्थित अधिकारियों की सुविधा के लिए Body Worn Cameras बॉडी वाउंड कैमरे भी उपलब्ध होंगे।

132. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा ई-परिवहन व्यवस्था के माध्यम से परिवहन क्षेत्र लर्नर लाइसेंस को छोड़कर लगभग हर सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2022-23 में इस सुविधा को भी ई-परिवहन व्यवस्था में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

133. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बनीं सड़कों की पार्सिंग के लिए निर्धारित मापदण्डों की समीक्षा की जाएगी तथा छोटे 4 पहिए वाहनों व छोटी बसों के लिए रोड पार्सिंग हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

134. वर्तमान में एम्बुलेंस के पंजीकरण के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे जिससे एंबुलेंसिंज का भी पंजीकरण हो सके तथा मापदण्डों के आधार पर उनका भी सावधिक (periodic) रखरखाव किया जा सके।

135. अध्यक्ष महोदय, एच0आर0टी0सी0 के बेड़े में अप्रैल माह तक 220 नई बसें सम्मिलित हो जाएंगे। वर्ष 2022-23 में 200 बसें क्रय की जाएंगी जिनमें से 50 छोटी इलैक्ट्रिक बसें 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत खरीदी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि :

मुश्किलें कितनी भी हों सामने हमारे,
हिम्मत हो तो रास्ता जरूर निकलता है,
जो खुद पर यकीन करके आगे बढ़ते हैं,
उनके साथ ही यह ज़माना चलता है।

136. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में 7 बस अड्डों का निर्माण पूरा करने के पश्चात् वर्ष 2022-23 में 8 और बस अड्डों क्रमशः ठियोग, भंजराडू, बरछवाड़, हरिपुर, देहरा, थुनाग, बंगाणा, नदौन तथा जंजैहली का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

137. मैंने पिछले अभिभाषण में माननीय सदन को सूचित किया था कि नीति आयोग ने 'इलैक्ट्रिक वाहन नीति' बनाने के लिए प्रदेश सरकार को "लाइट हाउस स्टेट" के रूप में चयनित किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश सरकार द्वारा इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021 को मंजूरी दे दी गई है। हमारी सरकार भारत सरकार के सहयोग से 'इलैक्ट्रिक व्हीकल्ज एण्ड कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग' पार्क स्थापित करेगी।

138. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों से राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता से 2 हजार 95 करोड़ रुपये की नई परियोजना स्वीकृत करवाई है। यह परियोजना क्रमशः 1,000 करोड़ रुपये तथा लगभग 1,095 करोड़ रुपये के दो चरणों में कार्यान्वित की जाएगी। इन दोनों चरणों के अंतर्गत शहरों का सौंदर्यकरण, धरोहर भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन, हेलीपोर्ट का निमार्ण, ईको-टूरिज्म वॉटर स्पोर्ट्स, वैलनेस सेंटर, Budhist Circuits, पर्यटन अधोसंरचना, युवाओं का प्रशिक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। आगामी वित्त वर्ष में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके इनकी निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इनमें प्रमुख तौर पर कन्वेंशन सेंटर, धर्मशाला, पालमपुर का सौंदर्यकरण, शिवधाम चरण-॥, बाबा बालक नाथ मंदिर का सौंदर्यकरण, वैलनेस सेंटर झटींगरी, कल्पा, रेणुकाजी इत्यादि परियोजनाएं शामिल हैं।

04/03/2022/1305/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

139. अध्यक्ष महोदय, गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बहुत से नये प्रयास किए हैं। मैं वर्ष 2022-23 में निम्न कार्यों को पूरा करना प्रस्तावित करता हूंः-

- क्यारीघाट में कन्वेंशन सेंटर।
- टाउन हाल, शिमला में लाइट एंड साउंड शो।

- फूड एण्ड क्राप्ट इंस्टीट्यूट धर्मशाला का इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के स्तर पर उन्नयन।

140. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में 'नई राहें, नई मंजिलें' योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत मण्डी में शिवधाम, लारजी तथा तत्तापानी में वॉटर स्पोर्ट्स बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग व चांशल को विकसित करना शामिल है।

141. अध्यक्ष महोदय, राज्य में अधिक-से-अधिक घरेलू व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र की भागीदारी से कुछ नये प्रयास किए जाएंगे जिनमें से निम्न प्रमुख हैः-

- नये पर्यटन गंतव्य पर जाने के लिए कारवां पर्यटन को प्रोत्साहन।
- पारंपरिक काठकुनी शैली को वास्तुकला वाले स्थानों को विभिन्न पर्यटक स्थलों से जोड़ना।
- कांगड़ा जिले में आर्ट गैलरी को पर्यटन सर्किट से जोड़ना।
- ऐतिहासिक विरासत को प्रसारित एंव प्रचारित करने के लिए प्रदेश के ऐतिहासिक किलों को पर्यटकों के आकर्षण के रूप में विकसित करना।
- माउंटिंग बाइकिंग ट्रैक शुरू करना।

142. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के दौरान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए 'Interest Subvention' योजना जारी रखी जाएगी। मैं यहां यह कहना चाहूगा कि :-

सबकी तकदीर बदलनी है, राह दिखानी है तुझे,
हाथों की लकीरों तक नहीं, उनसे आगे जाना है मुझे।

वन सरंक्षण एवं
वनों से रोज़गार

143. अध्यक्ष महोदय, सत्त विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक राज्य के 30 प्रतिशत क्षेत्र को वन आवरण अधीन लाया जाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2022-23 में 15 हजार हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा।

144. ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फूलों और हिमालयन वनस्पतियों पर आधारित 20 नेचर ट्रेल्ज विकसित किए जाएंगे।

145. जंगलों में भूमि कटावा रोकने और नमीं को बढ़ाने हेतु 25 करोड़ रुपये की लागत से 125 स्थानों पर बांध निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में जलाश्यों के आसपास के क्षेत्रों को ईको-टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

146. अध्यक्ष महोदय, चीड़ के जंगलों में स्थानीय समुदायों को बहुत सीमित आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। समुदाय के सहयोग से वर्ष 2022-23 में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में चीड़ के पेड़ों के स्थान पर चौड़ी पत्ती वाले पौधे रोपित किए जाएंगे। इससे पशुओं के लिए चारा मिलेगा, जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं कम होंगी तथा भूमि कटाव रोकने में भी सहायता मिलेगी।

147. अध्यक्ष महोदय, वन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही 3 बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाएंगे :-

- 6 जिलों क्रमशः बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, मण्डी तथा शिमला के 260 ग्राम पंचायत वार्डों में 50 करोड़ की लागत से आजीविका सर्जन तथा अन्य विकास गतिविधियां की जाएंगी।
- 100 करोड़ रुपये की लागत से 428 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजनाएं चलाई जाएंगी।
- कांगड़ा और चम्बा जिला में 40 करोड़ रुपये की लागत से 150 वॉटर रिचार्ज जोन्ज का स्प्रिंग्जशैड एप्रोच के अंतर्गत उपचार तथा कट रुट स्टोक

(सी0आर0एस0) विधि से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में लैंटान उन्नमूलन कार्य किया जाएगा और उस भूमि पर उपयोगी प्रजातियों का रोपण किया जाएगा।

148. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लगभग 63 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे जिस पर 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके लिए वृक्षारोपण, भू-संरक्षण, जल भण्डारण, पर्यावरण, पर्यटन जैसे कार्य किए जाएंगे।

पैरा 149. एन0एस0 द्वारा ... जारी ।

04-03-2022/1310/NS/AG/1

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

149. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले वर्ष नवम्बर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (COP-26) में अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पांच अमृत तत्व प्रस्तुत किए जिसमें गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 GW तक पहुंचाने व अक्षय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को वर्ष 2030 तक पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश की शत-प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा एवं ग्रीन ऊर्जा से पूर्ण किया जाए। इससे एक ओर हिमाचल प्रदेश देश का पहला पूर्णतः ग्रीन स्टेट बन जाएगा वहीं दूसरी ओर इस प्रमाणन से राज्य में निर्मित उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए।

150. शिमला-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लिए एक "Green-e-Mobility" कार्यक्रम का एक प्रस्ताव बाह्य द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत परिवहन संचालन व्यवस्था, Charging Station Network तथा ई-बैटरियों की रिप्लेसमैंट का प्रावधान किया जाएगा।

151. प्लास्टिक कचरे के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रदेश में प्लास्टिक कचरे की Value Chain के प्रभावी प्रबंधन हेतु Extended Producer Responsibilty हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा।

152. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 में जर्मनी सरकार की संस्था GIZ के सहयोग से वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी तथा एक हज़ार गरीब किसानों के लिए इस नीति पर आधारित Demonstration Model स्थापित किए जाएंगे।

153. वर्ष 2022-23 में Geographical Indication Act- 1999 के अंतर्गत राज्य के उत्पादों जैसे लाल चावल, किन्नौरी सेब, मण्डी की सेपूबड़ी, हिमाचली टोपी, सिरमौरी लोईया, हिमाचली धाम, थाची (मण्डी) धातु शिल्प, हिमाचली वाद्य यन्त्रों तथा किन्नौरी आभूषणों के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

154. राज्य में Integrated Solid Waste Management से संबंधित प्रस्तावों को ऑनलाइन स्वीकृति देने तथा आवेदनों की ऑनलाइन मोनिटरिंग के लिए एक आधुनिक पोर्टल की स्थापनी की जाएगी।

155. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का एक-एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मण्डी तथा ऊना में स्थापित किया जाएगा ताकि बोर्ड प्रभावी ढंग से काम कर सके। शिमला और पांवटा साहिब स्थित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में निरीक्षण एवं परीक्षण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इनकी संबद्धता National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratories (NABL) के साथ सुनिश्चित की जाएगी।

156. वर्ष 2022-23 में प्रदेश में स्थित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों पर 14 नए निगरानी केंद्रों की स्थापना की जाएगी जोकि नदियों के जल की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् Robert James Brown के कथन, जिसमें कि उन्होंने Green Growth के महत्व को बतलाया है, का वर्णन करना चाहूंगा जोकि चिंता और चिंतन का विषय हैः-

"भविष्य या तो हरा होगा या तो नहीं होगा"

डिजिटाईजेशन

157. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, वन संरक्षण, भू-सर्वेक्षण, कृषि एवं बागवानी, आपदा प्रबंधन, खनन् इत्यादि क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग की असीमित संभावनाएं हैं। अतः मैं चार स्तम्भों क्रमशः सक्षम शासन, ड्रोन मेले और महोत्सव, सक्षम नीतिगत ढांचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर आधारित एक नई "Governance and Reforms Using Drones (GARUD)" योजना आरम्भ करने की घोषणा करता हूं।

158. वर्ष 2022-23 में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश में चार फ्लाईंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। सरकारी विभागों के साथ-साथ राज्य के युवा भी ड्रोन संबंधित प्रशिक्षण पाकर रोज़गार के अवसर का लाभ उठा सकेंगे।

04-03-2022/1315/NS/AG/1

159. वर्ष 2022-23 में गवर्नेंस को और प्रभावी बनाने के लिए निम्न कदम उठाए जाएंगेः-

- हमीरपुर जिला में पायलट आधार पर आरम्भ किए गए 'स्वामित्व' कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले का सर्वेक्षण समाप्त किया जाएगा तथा सभी आबादी देह क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को भू-स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
- e-District के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या को मौजूदा 96 से बढ़ा करके 150 किया जाएगा।
- प्रदेश के छात्रों की सुविधा के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी मटीरियल ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- सरकारी योजनाओं में pilferage रोकने के लिए बाउचर आधारित e-RUPI प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा।
- ट्रेकर्ज़ को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेकर इनफॉर्मेशन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
- दस पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक स्थलों में WiFi हॉटस्पोट स्थापित किए जाएंगे।
- लिटिगेशन मोनिटरिंग सिस्टम (LMS) को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि सभी कोर्ट केसिज की अद्यतन स्थिति को लिटिगेशन मोनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से देखा जा सके।

- सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए फैमिली रजिस्टर डाटा बेस को अपडेट किया जाएगा।
- राहत कोष से प्रदेश के असहाय और जरूरतमंद लोगों का आर्थिक सहायता देने हेतु एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से राहत वितरण की वर्तमान प्रक्रिया को स्वचालित किया जाएगा।

160. मैं सरकारी योजनाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान डाटा सेंटर को अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 38 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा

उनका यही है दावा कि सूरज उन्हीं का है,

मेरी यह जिद्द है कि सबको एक ही धूप मिले।

भू-प्रशासन एवं

आपदा प्रबन्धन

161. अध्यक्ष महोदय, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमैंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित ऑनलाइन नेशनल One Nation-One Registration के अनुरूप इस प्रणाली को राजकोष एवं भू-अभिलेखों के साथ integrate करके इसे और प्रभावी और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

162. Geological Survey of India (GSI) की मदद से किन्नौर जिला में भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू की जाएगी। तदोपरान्त अन्य संवेदनशील जिलों में भी यह प्रणाली चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी जिसके लिए विस्तृत योजना रिपोर्ट बनाकर वित्त पोषण हेतु National Disaster Management Authority को प्रेषित किया जाएगा।

163. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की 'आपदा मित्र योजना' के अंतर्गत 1 हजार 500 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

राजस्व संसाधन

164. अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के कारण देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के कर राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रदेश

सरकार के प्रयत्नों एवं लॉकडाउन के खुलने के उपरांत कर राजस्व में भी आशानुसार बढ़ोतरी हो रही है जोकि हर्ष का विषय है। वर्ष 2022-23 में 9 हजार 282 करोड़ रुपये कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2022-23 में कर राजस्व में वर्ष 2021-22 के अनुमानों की अपेक्षा 15 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है जोकि प्रदेश केा प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में मददगार सिद्ध होगी।

4.03.2022/1320/RKS/DC-1

कर एवं आबकारी

165. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नशे के दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्तन (enforcement) को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा।

166. हिमाचल प्रदेश एकीकृत नशा निवारण एवम् ड्रग्स नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा नशा निवारण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों/निगमों एवम् संस्थाओं के समन्वय के लिए आबकारी विभाग में एक नशा निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

167. हमारी सरकार द्वारा घोषित 'टैक्स हाट' की सफलता और लोकप्रियता के दृष्टिगत मैं घोषणा करता हूँ कि GST एकत्रिकरण व्यवस्था को और सरल तथा सुदृढ़ बनाने के लिए एक GST प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

168. कर एवं आबकारी विभाग में करदाताओं की सुविधा हेतु ।T पर आधारित एक समर्पित व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। इससे करदाताओं तथा व्यापारी वर्ग के लिए GST अनुपालना और सुविधाजनक हो जाएगी ।

169. हाल ही में हुए अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनर्वृति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जांच हेतु एक मोबाइल App आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस

मोबाइल App के माध्यम से बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन करने से ही शराब के वैध स्त्रोत का पता चल सकेगा।

170. गौवंश सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर एक रुपया का अतिरिक्त Cess लगाया जाएगा।

श्रम एवं रोज़गार

171. अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल के अनुभवों से सीख लेते हुए हमारी सरकार online रोज़गार मेले आयोजित करेगी। वर्ष 2022-23 में 9 रोज़गार मेलों व 120 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ रोज़गार कार्यालयों में registration की पूरी प्रक्रिया की digitization की जाएगी।

गृह/कानून व्यवस्था

172. अध्यक्ष महोदय, मैं अपराध का पता लगाने और इसकी रोकथाम के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड-एण्ड-कंट्रोल सेंटर (CCC) की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इन केन्द्रों की सहायता से CCTV तथा Integrated Traffic Management System (ITMS) के माध्यम से प्रभावी निगरानी की जाएगी। यह केन्द्र अवैध खनन, शराब की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों पर रोक लगाने में सक्षम होंगे। इसके लिए 7 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

173. साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय शिमला में केवल एकमात्र पुलिस स्टेशन है। मैं घोषणा करता हूँ कि धर्मशाला और मण्डी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे।

174. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने आपातकाल के दौरान मीसा, DIR, CrPC के अधीन राजनीतिक व सामाजिक कारणों से कारावास व पुलिस स्टेशनों में अनिरुद्ध रहे व्यक्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना

आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत 1 से 15 दिनों तक कारावास व पुलिस स्टेशनों में निरुद्ध रहे व्यक्तियों को 8 हजार व 15 दिनों से अधिक समय तक निरुद्ध रहे व्यक्तियों को 12 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस राशि को बढ़ाकर में क्रमशः 12 हजार रुपये तथा 20 हजार रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

4.03.2022/1325/RKS/DC-1

175. पुलिस आवास, पुलिस चौकियों, पुलिस थाने और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों जैसे पुलिस प्रशिक्षण और राज्य आपदा रिस्पाँस बल प्रतिष्ठानों में ढाँचागत विकास और पूँजीगत कार्यों तथा आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध करवाने में गति दी जाएगी। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

176. प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में आग जैसी दुर्घटनाओं की स्थिति में तुरन्त राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मैं वर्ष 2022-23 में 4 नये अग्निशमन केन्द्र खोलने और 5 अग्नि शमन पोस्टों को अग्निशमन उपकेन्द्र के रूप में उन्नयनित करने की घोषणा करता हूँ।

177. मैं गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का Rank Allowance भी बढ़ाया जाएगा।

<u>भाषा, कला एवं संस्कृति</u>

178. अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष स्वतन्त्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने प्रदेश के विशिष्ट पहचान वाले 75 गाँवों का चयन किया है। इन गाँवों को देश के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना लागू की जाएगी। इससे इन गाँवों और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत पर्यटन की दृष्टि से भी देश और दुनिया के सामने आ सकेगी। इन गाँवों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विशिष्टता को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों, पुस्तकों और अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा।

179. सरकार ने वर्ष 2021 में सांस्कृतिक नीति की घोषणा की थी। इस नीति में घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रारम्भ में 2 करोड़ रुपये की राशि से सांस्कृतिक कोष गठित करने की मैं घोषणा करता हूँ।

180. स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि के रूप में में घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में एक "**लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय**" की स्थापना की जाएगी।

181. स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी की पावन स्मृति में प्रदेश सरकार हिमाचली लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए, "**लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान**" प्रारम्भ करेगी जोकि प्रति वर्ष लोक गायन के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।

182. शिमला के बैंटनी कैसल (Castle) के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में है। इसे शीघ्र ही शिमला शहर के इतिहास, कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में जनता को समर्पित किया जाएगा।

183. बिलासपुर में गोबिन्द सागर के निर्माण के समय जो मन्दिर पानी में समा गए थे को पुनःस्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना तैयार की गई है। 1 हजार 400 करोड़ रुपये की इस परियोजना का प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भेजा जाएगा।

जब तक संस्कृति है तब तक आस है,
बिना संस्कृति के मानव का विनाश है ॥

184. बहुउद्देशीय साँस्कृतिक केन्द्र, कुल्लू का निर्माण लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है। ऊना के सांस्कृतिक केन्द्र का लोकार्पण भी कर दिया गया है। बिलासपुर, मण्डी और सोलन में इन केन्द्रों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। ये सभी वर्ष 2022-23 में पूरे कर लिए जाएंगे जिन पर लगभग 22 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। चम्बा व नाहन में बन रहे केन्द्रों के निर्माण कार्य को भी गति दी जाएगी।

185. प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार संस्कृति मन्त्रालय के सहयोग से 100 करोड़ रुपये की लागत से स्पिति के ताबो में 'भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान' की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 7.87 हैक्टेयर भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में इसका निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल

186. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य खेल संस्थान की स्थापना करने की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन की मैं घोषणा करता हूँ।

187. प्रदेश में त्रिस्तरीय खेल महाकुम्भ का आयोजन सांसदों और विधायकों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, एथेलेटिक्स, वालीबॉल, बास्केटबाल और कुश्ती खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा जो जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान में सहायक सिद्ध होगा।

188. मैं वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित Indoor तथा Outdoor खेल परिसरों के लोकार्पण की घोषणा करता हूँः-

- नूरपुर में pre-fabricated बहुउद्देशीय हॉल।
- जंजैहली में indoor स्टेडियम।
- सरकारी महाविद्यालय बंगाणा में बहुउद्देशीय हॉल।
- माजरा (सिरमौर) में Hockey Astroturf Field
- सरस्वती नगर में 8 Lane 400 Meter SyntheticTrack
- 10 करोड़ रुपये की लागत से टाण्डाखोली, जिला काँगड़ा में प्रस्तावित इण्डोर स्टेडियम का निर्माण शुरु किया जाएगा।

  इन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

श्री बी.एस. द्वारा जारी

04.03.2022/1330/बी.एस./डी0सी0/-1

189. सरकार स्वैच्छिक युवा क्लबों और विशेष रूप से युवाओं के क्षमता निर्माण को और मजबूत करेगी। सर्वश्रेष्ठ तीन युवा मंडलों को वार्षिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल घोषित कर पुरस्कृत किया जाएगा। जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को 51 हजार रुपए, द्वितीय स्थान पाने वाले को 31 हजार रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 21 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

190. अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली खेल-कूद प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाइट मनी को मैं प्रदेश के अन्दर 120 रुपए से बढ़ा करके 240 रुपए प्रतिदिन तथा प्रदेश के बाहर 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति दिन करने की सहर्ष घोषणा करता हूं।

जनजातीय विकास

191. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जनजातीय वर्ग की एक बहुत बड़ी संख्या गैर-जनजातीय क्षेत्रों में रह रही है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों से बाहर रह रहे जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए उचित कार्य योजना तैयार की जाएगी।

192. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में देश की उत्तरी सीमा के साथ लगते क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए Vibrant Villages Programme घोषित किया गया है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए उचित कार्य योजना तैयार करके इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की जाएगी।

वैकल्पिक यातायात

193. अध्यक्ष महोदय, लैंड लॉक्ड पहाड़ी राज्य होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में सड़क के अलावा यातायात के बहुत सीमित विकल्प उपलब्ध हैं। हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से विगत वर्षों में इस परिदृश्य को परिवर्तित करने का सशक्त प्रयास किया है। मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में निर्माणधीन तीन रेल लाइनों क्रमशः भानूपल्ली-

बिलासपुर-बैरी के लिए 1,868 करोड़ रुपए, नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 335 करोड़ रुपए तथा मद्दी-चण्डीगढ़ रेल लाइन के लिए 450 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधन किया है। इन प्रावधानों के माध्यम से इन रेल लाइनों के कार्यान्वयन को गति मिलेगी। हमारी सरकार राज्य अंशदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

194. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पांवटा साहिब-जगाधरी रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर रेल मंत्रालय द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जाएगी। इसके साथ ही भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा ऊना-हमीरपुर नई रेल नाइन के निर्माण की लागत के अंशदान पर भी सहमति बनाई जाएगी।

195. अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित 'पर्वत माला-राष्ट्रीय रज्जू मार्ग विकास कार्यक्रम' योजना प्रदेश के लिए हितकारी सिद्ध होगी। योजना के अन्तर्गत रोपवेज को, निजी भागीदारी से सड़क मार्ग के विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे कि पर्यटन तथा दैनिक आवाजाही में सुविधा होगी। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में चार रज्जू मार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार के साथ समौझता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाएंगे। इस नई योजना के लिए मैं भारत सरकार का आभारी हूं।

196. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप नाबार्ड तथा भारत सरकार ने प्रदेश में रज्जू मार्ग को नाबार्ड के Rural Infrastructure Development Fund(RIDF) के माध्यम से ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश में रज्जू मार्ग बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाएगी। निर्माणाधीन बगलामुखी रज्जू मार्ग का वर्ष 2022-23 में लोकार्पण कर दिया जाएगा।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

04.03.2022/1335/बी.एस./डी0सी0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

197. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है कि आखिरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बल्ह में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण को तकनीकी रूप से स्वीकार कर लिया गया है, यह हवाई अड्डा, उपकरण व रात्रि लैडिंग सुविधाओं के साथ, एयर बस 320 जैसे बड़े विमानों को उतारने में सक्षम होगा। इसके निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करने के पश्चात भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी।

198. अध्यक्ष महोदय, वैकल्पिक यातायात सुविधाओं के सृजन के लिए वर्ष 2022-23 के दो हजार करोड़ रुपए राज्य कोष से व्यय किए जाएंगे।

अवासीय सुवधिाएं

199. अध्यक्ष महोदय, मैंने 2020-21 के बजट अभिभाषण में 'स्वर्ण जयंती आश्रय' योजना आरंभ करते हुए अनुसूची जाति वर्ग के सभी पात्र लंबित आवेदकों को आवासीय सहायता देने की घोषणा की थी। हमारी सरकार की इस प्रतिबद्वता को दोहराते हुए मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि गत दो वर्षों में सभी श्रेणियों सहित 22 हजार लाभार्थियों को विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्ययों से सहायता प्रदान की जा चुकी है। इनमें जन जातीय क्षेत्रों में तथा इससे बाहर रह रहे जनजातीय वर्ग के लाभार्थी भी सम्मिलित हैं।

200. मैं पूर्व की घोषणा के अनुसरण में वर्ष 2022-23 में कुल 12,769 लाभार्थियों को आवासीय सुवधिाएं प्रदान की जाएंगी। योजनावार लक्ष्य निम्न प्रकार से रहेगाः-

* 'मुख्य मंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत 1,533 आवास।

* 'प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के अन्तर्गत 1,262 आवास।

* 'प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)' के अन्तर्गत 2,346 आवास।

04.03.2022/1200/बी.एस./डी0सी0/-2

* 'स्वर्ग जयन्ती आश्रय योजना' के अन्तर्गत शेष बचे सभी 7,628 आवास।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा किः-

ख्वाब देखें हैं, हौंसले भी अभी जिंदा हैं,
हम वो हैं जिनसे, मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं

भर्तियां

201. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हमेशा ही फंक्शंनल पदों को भारने को प्राथमिकता दी है। आगामी वर्ष में भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर, नर्सें, रेडियोग्राफर, ओ0टी0 सहायक, लैब टैक्निशियन, Dental Hygienist, फार्मासिस्ट, MRI टैक्निशियन, ई0सी0जी0 टैक्निशियन तथा अन्य टैक्निशियनों के पद आदि शामिल हैं, 780 आशा कार्यकताओं के नए पद भरे जाएंगे साथ ही 437 पद आशा फैसिलीटेटर, 870 Community Health Officer के पद भी भरे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के 264 पद भी भरे जाएंगे। हमीरपुर, नाहन, चम्बा तथा नेरचौक में स्थित नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में समुचित फैकल्टी तथा अन्य श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।

202. इसके इतिरिक्त विभिन्न विभागों में खाली फंक्शंनल पदों को भी सरकार भरेगी। जल शक्ति विभाग में पैराफिटर, पंप ऑपरेटर तथा Multi Task Part Time Workers शामिल हैं, भरे जाएंगे। जिनमें शिक्षा विभाग में विभन्न शिक्षकों की भर्ती, पुलिस आरक्षी भर्ती, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद जैसे लाइनमैंन, जुनियर टी मेट इत्यादि, एच0आर0टी0सी0 में ड्राइवर तथा कंडक्टर इत्यादि की आवश्यक भर्तियां, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायत सचिव,

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

04-03-2022/1340/एच.के.-एन.जी. /1

मुख्य मंत्री..... जारी

पैरा संख्या - 202...जारी

पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक, विभिन्न विभागों में लिपिक, JOA (IT), तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवं इंस्ट्रक्टर, रेशम विभाग के इंस्पेक्टर तथा विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आदि शामिल हैं। आगामी वर्ष में शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग में अंशकालीन मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। गृह रक्षकों की नई भर्ती कई वर्षों से नहीं हो रही है। आगामी वर्ष में गृह रक्षकों की आवश्यक भर्ती करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार 30,000 रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाएगी।

कर्मचारी कल्याण

203. अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों का कल्याण हमेशा ही मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। मैं सरकारी आवासों के रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए वर्ष 2022-23 में 37 करोड़ रुपये और सरकारी आवासों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

204. अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की पैंशन योजना है जिसके तहत 5,000 रुपये तक की मासिक पैंशन 60 वर्ष के बाद, नागरिकों को अंशदान के हिसाब से मिलती है। इस समय प्रदेश में 'अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। योजना के तहत श्रमिक, गृहिणी, व्यापारी वर्ग, किसान, बागवान और स्वरोजगारी युवाओं के लिए प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 में 15 करोड़ रुपये का सरकारी अंशदान उनकी पेंशन निधि के लिए प्रदान करेगी। सरकार इस समय योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति वर्ष तक का अंशदान प्रदान करती है ।

04-03-2022/1340/एच.के.-एन.जी. /2

205. हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों से जुड़े सभी पैरा वर्कर्ज़ को इस योजना से आगामी वर्ष में जोड़ा जाए। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मैं प्रदेश सरकार के अंशदान की मौजूदा सीमा को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति वर्ष करने की सहर्ष घोषणा करता हूं। साथ ही वर्तमान और नए लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना के तहत देय सरकारी अंशदान की समय सीमा को मैं दिनांक 31-03-2023 तक बढ़ाने की भी मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। इससे 1,50,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा परिणामस्वरूप हमारा प्रदेश Universal सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

206. आऊटसोर्स कर्मियों से सम्बन्धित शिकायतों को मेरी सरकार ने गम्भीरता से लिया है। मेरी बजट घोषणा के अनुरूप दिसम्बर माह में सरकार ने एक मॉडल टेंडर सभी विभागों से सांझा किया है। इस मॉडल टेंडर के अनुसार हर कर्मी को एक पे-स्लिप देना अनिवार्य कर दी गई है। इस पे-स्लिप में सर्विस प्रोवाइडर कर्मी को लिखित रूप से समस्त कटौतियों जैसे EPF इत्यादि एवं कर्मी को प्राप्त होने वाले Net Wages को दिखाना होगा। श्रम विभाग इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। मेरे हर बजट में न्यूनतम दिहाड़ी में प्रभावी बढ़ौतरी हुई है जिसका सीधा लाभ आऊटसोर्स कर्मियों को मिला है।

207. प्रदेश की विकास यात्रा में कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज़ का अतुलनीय योगदान है। कोरोना काल में इन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सेवायें दी हैं। हमारी सरकार इनके कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है एवं विगत चार बजटों में इनके मानदेय में यथासम्भव वृद्धि की है। आगामी वर्ष के लिए मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित है :-

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

04-03-2022/1345/एच.के.-एन.जी. /1

मुख्य मंत्री..... जारी

- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को 1,700 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 9,000 रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा करता हूं। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 4,550 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।
- मिनि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को 900 रुपये मासिक बढ़ौतरी के साथ अब 6,100 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3,100 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- आंगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 900 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 4,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,600 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- अध्यक्ष महोदय, आशा वर्कर्ज़ का कोविड के इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आशा वर्कर को 1,825 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 4,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3,700 रुपये की प्रतिमाह बढ़ौतरी की गई। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर को भारत सरकार का अंशदान तथा Incentives दिये जाने का भी प्रावधान है।
- सिलाई अध्यापिकाओं को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,950 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,650 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- मिड-डे-मील वर्कर्ज़ को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,900 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- जल रक्षक को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,800 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- हाल ही में नियुक्त हुये जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,900 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पैरा फिटर तथा पम्प ऑपरेटर को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- दिहाड़ीदारों को 50 रुपये बढ़ौतरी साथ के 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में न्यूनतम 140 रुपये प्रतिदिन अर्थात 4,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- इसके साथ हमारी सरकार के कार्यकाल में आऊटसोर्स कर्मियों की दिहाड़ी में न्यूनतम 4,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी हो जाएगी। प्रत्येक आऊटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पंचायत चौकीदार को 900 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,350 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई। पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से सम्बन्धित एक स्पष्ट नीति बनाई जाएगी क्योंकि उनकी यह मांग बहुत लम्बे समय से है। उनकी समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाएंगे।

04-03-2022/1345/एच.के.-एन.जी. /3

- राजस्व चौकीदार को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।
- राजस्व लम्बरदार को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,700 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

श्री जे.एस. द्वारा जारी.....

04.03.2022/1350-1355/जेएस/वाईके/1

- SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी। SMC शिक्षकों की सेवाओं को यथावत् रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है कि जहां हमारे SMC के अध्यापक लगे हैं, वहां उनको यथावत रखा जाएगा उनको वहां से नहीं हटाएंगे। इन अध्यापकों की सेवाओं से सम्बन्धित नीति बनाने के बारे में भी विचार किया जाएगा।
- IT Teachers को 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।
- SPOs को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी। खासतौर से चम्बा जिला और लाहौल में हमारे जो SPOs लगे हैं, मुझे कल उनका डैपुटेशन भी मिला था तो उसमें उनको 900 रुपये की बढ़ौत्तरी करेंगे। मैं यहां कहना चाहूंगा किः-

हर एक का दर्द सीने में ले के चलते हैं,
सब के दामन को खुशियों से भरते हैं।
यही चाहते हैं न रहे कोई जरूरतमन्द,
दिन रात सब के सपनों को पूरा करते हैं।

बजट अनुमान

208. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 के लिए 51 हजार 365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।

209. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2021-22 के संशोधित अनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 37 हजार 312 करोड़ रुपये हैं।

2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 37 हजार 34 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 278 करोड़ रुपये का राजस्व surplus अनुमानित है।

210. वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियां 36 हजार 375 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 40 हजार 278 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व

घाटा 3 हजार 903 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9 हजार 602 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.98 प्रतिशत है।

211. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमानों में नए कर का प्रस्ताव नहीं है। मुझे विश्वास है कि प्रभावी कर अनुपालन, भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

212. 2022-23 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये में से, वेतन पर 26 रुपये, पैंशन पर 15 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 11रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये, जबकि शेष 29 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है।

213. कोरोना के बावजूद विकास की गति को बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को GDP के 3 प्रतिशत से अधिक ऋण लेने की अनुमति प्रदान की है। इस कारण से

प्रदेश के Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस बारे संशोधन विधेयक इसी सत्र में सदन में लाया जाएगा। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

वक्त की हलचल से घबराते नहीं हम,
हमारे हौंसले मुश्किलों में पलते हैं।
रुकते नहीं हम बाधाओं को देख कर,
हम वो चिराग हैं जो आँधियों में जलते हैं ।।

214. अध्यक्ष महोदय, इस बजट के मुख्य बिन्दु संलगित अनुबन्ध में निहित हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी विनम्रता से इस सदन का आभार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूँगा कि मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल का 5वां एवं अन्तिम बजट प्रस्तुत किया है। मेरे लिए यह अत्यन्त गौरव और प्रसन्नता का विषय है तथा मैंने इस दौरान बहुत

कुछ नया सीखा है। हमारे लिए विगत् दो वर्ष अप्रत्याशित रूप से चुनौतीपूर्ण रहे क्योंकि इससे पूर्व किसी भी सरकार को महामारी और वैश्विक मन्दी का सामना एक साथ नहीं करना पड़ा। इस महामारी से जीवन के समस्त पहलू प्रभावित रहे। हमें एक साथ सभी मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा।

इस कार्यकाल में वित्तीय बाधाओं का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए हमने सामाज के सभी वर्गों, विशेषकर उन वर्गों, जिन्हें सरकार द्वारा सहायता की अधिक अपेक्षा होती है, की सेवा करने का प्रयास किया है। सामान्यतः पूर्व सरकारें समाज के ज़रूरतमन्द वर्गों के बारे में चुनाव के नज़दीक ही चिन्ता करना आरम्भ करती हैं किन्तु हमारी सरकार ने पहले बजट से ही सर्वजन कल्याण के लिए आवश्यक तथा प्रभावी कदम उठाये हैं।

मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट इस सदन में पहले प्रस्तुत बजटों से कहीं अधिक सम्पूर्ण एवम् समावेशी है। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रणाली में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान महिलाओं में उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए की गई घोषणाओं की ओर आकर्षित करता चाहूंगा।

इस बजट में सभी कर्मचारी वर्गों एवं पैरा-वर्कर्ज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट महिला सशक्तिकरण तथा अनुसूचित जाति एवम् जनजाति वर्गों के कल्याण पर केन्द्रित है।

अध्यक्ष महोदय, जन कल्याण के साथ-साथ यह बजट विकासोन्मुखी भी है। इस बजट में पूंजीगत व्यय के माध्यम से बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण पर बल दिया गया है। मैं यह बजट प्रत्येक हिमाचलवासी के समृद्ध भविष्य के प्रति समर्पित करता हूं।

जो रुक गया उसे क्या मुश्किलों से,
जो चलेगा उसी के पाँवों में छाला होगा।
औरों का दर्द होना चाहिए सीने में,
जो जलेगा उसी दीये से उजाला होगा।।

04.03.2022/1350/जेएस/वाईके/4

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन को संस्तुत करना चाहूंगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट पर यहां पर सार्थक चर्चा होगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा, जो हमारे कर्मचारी भाई अपनी OPS को ले कर आंदोलित हैं, उनकी भावनाएं हम तक पहुंची हैं। मैं उन भावनाओं का सम्मान करता हूं और हमने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। जो भी सुझाव होंगे, समाधान की दृष्टि से इसका क्या रास्ता हो सकता है, उनके सुझावों का स्वागत होगा। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि बातचीत के लिए वे जब भी चाहे, जिससे भी चाहें, आ सकते हैं और मिलकर

प्रदेश के विकास में क्योंकि कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसको स्मरण करते हुए हम उनसे इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर सहर्ष हम सभी के साथ बैठकर, बातचीत का रास्ता अपनाकर इस समस्या का, उनकी मांग का सकारात्मक दृष्टि से जो समाधान किया जा सकता है, उस दिशा में विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बजट पर सार्थक चर्चा हो और उसके साथ हम आगे बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक शनिवार, 05 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 04 मार्च, 2022 **सचिव।**